चिंतन

सीएए से पात्र शरणार्थियों को मिल रहे अधिकार

लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सेक्युलर सिविल कोड (धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता) की बात छेड़ कर यूसीसी (यूनिफार्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता) की बहस को तेज कर दी है, इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाण पत्र देकर सरकार की मंशा को साफ कर दिया है कि वह अल्पसंख्यकों के लिए खड़ी है। सीएए के विधेयक से लेकर कानून बनने तक काफी विरोध हुआ था, इसके बाद भी सरकार ने कदम पीछे नहीं खींचे थे। आज जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ लक्षित हिंसा हो रही है, तो सहज ही समझ में आती है कि भारत के लिए सीएए बनाना क्यों जरूरी था? कायदे से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई आदि अल्पसंख्यक शरणार्थियों के लिए भारत एक मूल देश की तरह है, इसलिए उन्हें अपनाना भारत का दायित्व है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि कांग्रेस तथा उसके सहयोगियों की अगुवाई वाली पिछली सरकारों की तुष्टिकरण की राजनीति के कारण देश में बड़ी संख्या में शरणार्थियों को नागरिकता अधिकार नहीं दिए गए। गुजरात में 188 हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाणपत्र दिया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लाखों शरणार्थियों को उनके अधिकार तथा न्याय देने के लिए है। शाह ने मुसलमानों को भी आश्वासन दिया कि सीएए में किसी की भी नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि यह नागरिकता देने के बारे में है। यह सही है कि अतीत में देश में अल्पसंख्यकों को तुष्ट करने के लिए राजनीति होती रही है, जिसके चलते वाजिब मुद्दे भी नेपथ्य में रहे हैं। नहीं तो देश में संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसके बावजूद समान नागरिक संहिता जैसे अहम प्रावधान लागू नहीं पाए, जबकि भारत जैसे विविध धर्म व संस्कृति वाले देश में समान नागरिक संहिता बहुत पहले लागू होनी चाहिए। कानून की नजर में सभी नागरिक समान है, इसलिए उन पर एक ही नियम कायदे लागू रहने चाहिए। सरकार को सीएए की तरह ही सेक्युलर नागरिक संहिता भी लेकर आना चाहिए। देश में अगर किसी भी रूप में गलत चीज हो रही है, तो उसके चेक व बैलेंस का नियम तो रहना ही चाहिए। कांग्रेस तथा उसके सहयोगियों की पिछली सरकारों की तुष्टिकरण की नीति के कारण शरण के लिए देश में आए लोगों को उनका अधिकार और न्याय 1947 से 2014 तक नहीं मिला। शरणार्थी अगर देश में रह रहे हैं और सरकार ने उन्हें रहने की अनुमति दी हुई है, तो उन्हें वैध तरीके से नागरिकता देने में हर्ज नहीं होना चाहिए, इससे वे शरणार्थी टेक्स सिस्टम में आएंगे, राष्ट्र के निर्माण में योगदान करेंगे। सीएए कानून पारित होने के बाद इस पर जमकर राजनीति भी हुई थी, जिसमें कांग्रेस समेत विपक्ष के अनेक नेताओं ने लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया कि इससे मुसलमानों के साथ अन्याय होगा और वे अपनी नागरिकता खो देंगे। जबकि तथ्यात्मक रूप से यह बात ही गलत है। भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, जबकि पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहां मुस्लिम बहुसंख्यक है। इन मुस्लिम बहुसंख्यक देशों में हिंदुओं पर अत्याचार होते रहे हैं, जिससे बचने के लिए वे भारत में शरणार्थी के रूप में रहने लगे थे। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ ताजा हिंसा उदाहरण है। सीएए से मदद मिल रही है। अब सरकार को यूसीसी की ओर बढ़ना चाहिए।

पीएम संबोधन
डॉ. जयंतीलाल भंडारी

ग्रामीण अर्थव्यवस्था संवरेगी

नि:संदेह इस समय किसानों की आमदनी बढ़ाने और देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संवारने के लिए सरकार की महत्वपूर्ण पहल उभरकर दिखाई दे रही है। गौरतलब है कि कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने के अभियान के तहत 11 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) परिसर के खेतों में जाकर 61 फसलों की 109 नई एवं उन्नत किस्में जारी करते हुए कहा कि इनसे देश में कम जमीन में अधिक पैदावार लेने और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। इससे महंगाई से भी बचाव होगा। कृषि भंडारण क्षमता के भौगोलिक स्तर पर उचित वितरण की डगर पर भी सरकार को आगे बढ़ना होगा।

15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकिले से देश को संबोधित करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया और कहा कि कृषि व्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा कृषि व ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। इसी के मद्देनजर इन दिनों प्रकाशित हो रही वैश्विक आर्थिक संगठनों और वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की रिपोर्टों में भारत में कृषि सेक्टर में सुधार और ग्रामीण खपत में वृद्धि के मद्देनजर भारत की विकास दर के अनुमान बढ़ाए जा रहे हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक (एडीपी) के द्वारा जारी रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की विकास दर को 6.7 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 फीसदी कर दिया गया है। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भारत की विकास दर अनुमान को 6.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 फीसदी, ओईसीडी ने 6.2 से बढ़ाकर 6.6 प्रतिशत, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने 6.3 से बढ़ाकर 7 प्रतिशत तथा फिच ने 7 से बढ़ाकर 7.2 प्रतिशत किया है। इसमें कोई दोमत नहीं है कि सरकार को इस वर्ष जो बेहतर मानसून विरासत में मिला है, उससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था रफ्तार से बढ़ रही है। पूरे देश के कोने-कोने में बेहतर मानसून के लाभ दिखाई देने लगे हैं। बेहतर मानसून से ग्रामीण इलाके में खपत बढ़ रही है।

बढ़ते हुए कृषि उत्पादन और ग्रामीण भारत के विकास के लिए सरकारी योजनाओं के तहत किए गए भारी व्यय तथा स्वरोजगार की ग्रामीण योजनाओं से ग्रामीण परिवारों की आमदनी में तेज इजाफे के साथ उनकी क्रय शक्ति बढ़ी है। ऐसे में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अधिक खर्च कर रहे हैं। कृषि संबंधी संसाधनों की अधिक बिक्री हो रही है, वरन गांवों में उपभोक्ताओं की खरीदारी भी उच्च स्तर पर है। यह सब ग्रामीण भारत में भविष्य के प्रति उत्साह और वर्तमान के बेहतर परिणामों का प्रतीक है। हाल ही में 12 अगस्त को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा महंगाई के आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2024 में खुदरा महंगाई दर घटकर 3.54 फीसदी रह गई है, जबकि जून 2024 में खुदरा महंगाई दर 5.08 प्रतिशत थी। खुदरा महंगाई दर पिछले 5 वर्षों के सबसे कम ऐसे स्तर पर पहुंच गई है, जो कि रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित 4 प्रतिशत के लक्ष्य से भी नीचे है। निःसंदेह इस समय किसानों की आमदनी बढ़ाने और देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संवारने के लिए सरकार की महत्वपूर्ण पहल उभरकर दिखाई दे रही है। गौरतलब है कि कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने के अभियान के तहत 11 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) परिसर के खेतों में जाकर 61 फसलों की 109 नई एवं उन्नत किस्में जारी करते हुए कहा कि इनसे देश में कम जमीन में अधिक पैदावार लेने और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल सकेगी। इससे महंगाई से भी बचाव होगा।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक वर्ष 2024-25 के बजट के तहत किसानों के कल्याण और कृषि को विकास का इंजन बनाने की रणनीति के तहत किसानों के हित में कृषि व ग्रामीण क्षेत्र की क्षमता के दोहन के जो अभूतपूर्व कदम आगे बढ़ाए गए हैं, उनसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकी जा सकेगी। इस बजट के माध्यम से कृषि सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये सुनिश्चित किए हैं। बजट के तहत शीघ्र खराब होने वाले सामान की बाजार में समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इस बजट में प्रभावी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। बजट के तहत उपभोक्ता मामलों के विभाग को दाम स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के लिए 10,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। जहां इस कोष का उपयोग दाल, प्याज और आलू के बफर स्टॉक को रखने के लिए किया जाएगा। प्राकृतिक खेती पर भारी प्रोत्साहन सुनिश्चित किए गए हैं और आगामी दो वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

इस बार वित्त मंत्री ने नए बजट में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने, दलहन-तिलहन को पैदावार बढ़ाकर और किसानों की आय बढ़ाने, बीज की समस्या के निराकरण और मुख्य फसलों की उत्पादकता प्रभावित होने जैसे मामलों को चुनौतियों को कम करने कृषि के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ज्यादा प्रावधान किए हैं। निश्चित रूप से सरकार के द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संवारने की डगर पर आगे बढ़ते हुए कई अहम बातों पर ध्यान दिया जाना होगा। कृषि प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल, कृषि में मशीनीकरण को बढ़ाए जाने, जलवायु अनुकूल कृषि-खाद्य प्रणाली अपनाएं जाने, अधिक ग्रामीण कच्ची सड़कों को मंडियों से जोड़ने, जैसी नीतिगत प्राथमिकताओं के साथ-साथ आपूर्ति श्रृंखला में सुधार से खाद्य वस्तुओं की महंगाई को नियंत्रित रखने के कारगर प्रयासों की डगर पर लगातार आगे बढ़ना होगा। चूंकि देश में फसल कटाई के बाद की उपयुक्त व्यवस्था न होने से 12 से 14 फीसदी तक खाद्यान्न और करीब 35 फीसदी तक सब्जी और फलों की पैदावार बर्बाद हो जाती है। ऐसे में बजट के तहत इस वर्ष खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के लिए जिस तरह खाद्य भंडारण और वेयरहाउसिंग के लिए ऋणों की राशि दोगुनी सुनिश्चित की गई है, उसके कारगर उपयोग पर ध्यान देना होगा। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार कृषि भंडारण क्षमता वर्ष 2023 में 14.5 करोड़ टन थी। अब उसे वर्ष 2030 तक दोगुना बढ़ाने की रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। कृषि भंडारण क्षमता के भौगोलिक स्तर पर उचित वितरण की डगर पर भी सरकार को आगे बढ़ना होगा।

जहां उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, पंजाब और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में तो अधिक भंडारण क्षमता है वहीं बिहार और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में इसकी भारी कमी है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना होगा कि ज्यादातर कोल्ड स्टोरेज में केवल एक ही फसल रखने की व्यवस्था होती है। अन्य फसलों के भंडारण की सुविधा इनमें नहीं होती। इसलिए अब देशभर में भंडारण क्षमता को उन्नत कर इनमें सभी या एक से अधिक कृषि उपज रखने की व्यवस्था की ओर भी ध्यान दिया जाना होगा। हम उम्मीद करें कि 11 अगस्त को सरकार ने 61 फसलों की 109 नई एवं उन्नत किस्मों से किसानों की आय बढ़ाने की जो पहल की है, उसके लाभों और प्रयोग के बारे में किसानों को उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। वर्ष 2024-25 के नए बजट से कृषि और ग्रामीण विकास को रफ्तार देने के जो रणनीतिक कदम बताए गए हैं, उनके क्रियान्वयन पर शुरुआत से ही ध्यान दिया जाएगा। इनके साथ ही सरकार द्वारा बेहतर मानसून की शक्ति को मुट्ठी में लेकर कृषि सुधारों की डगर पर तेजी से आगे बढ़ा जाएगा। ऐसे में जहां छोटे किसानों व ग्रामीण भारत के करोड़ों लोगों की खुशियां बढ़ेंगी, वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकेगी।

(लेखक खाद्य अर्थशास्त्री हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

रक्षाबंधन

श्वेता गोयल

शालीन एवं सात्विक स्नेह संबंधों का पावन पर्व

भाई-बहन के बीच अटूट बंधन, स्नेह और विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व सदियों से ही भारतीय जनमानस का अभिन्न अंग है। प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाए जाने वाले इस पर्व की भारतीय समाज और संस्कृति में बड़ी महत्ता है। रक्षाबंधन पर्व इस वर्ष 19 अगस्त को मनाया जा रहा है। भाईयों की कलाई पर राखियां बांधने के लिए बहनें इस दिन का वर्षभर इंतजार करती हैं। यह पर्व रक्षा के तात्पर्य से बांधने वाला एक ऐसा सूत्र है, जिसमें बहनें अपने भाईयों के माथे पर तिलक लगाकर जीवन के हर संघर्ष तथा मोर्चे पर उनके सफल होने तथा निरन्तर प्रगति पथ पर अग्रसर रहने की ईश्वर से प्रार्थना करती हैं तथा उनके सुखद जीवन के लिए मंगलकामना करती हैं। भाई भी अपनी बहनों को हर प्रकार की विपत्ति से रक्षा करने का वचन देते हैं।

मान्यता है कि सावन माह की पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में बांधे गए रक्षासूत्र का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है। वैसे तो हिन्दू समाज में रक्षाबंधन बहनों द्वारा भाईयों को रक्षा-सूत्र बांधने के पर्व के रूप में प्रचलित है लेकिन पूर्व में यह पर्व भाई-बहन तक ही सीमित नहीं था बल्कि विपत्ति आने पर अपनी रक्षा के लिए अथवा किसी की आयु और आरोग्य की वृद्धि के लिए किसी को भी रक्षा-सूत्र बांधा या भेजा जाता था। किसी भी धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान के बाद आज भी रक्षा-सूत्र के माध्यम से ही सभी उपस्थितजनों को रक्षा का संकल्प कराया जाता है। भारतीय परम्परा में विश्वास का बंधन ही मूल है और इसी विश्वास का बंधन है रक्षाबंधन। बहन द्वारा भाई को रक्षा-सूत्र बांधने का चलन कब शुरू हुआ, इसकी कोई सटीक प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती लेकिन रक्षाबंधन मनाए जाने के संबंध में अनेक पौराणिक एवं ऐतिहासिक प्रसंगों का उल्लेख अवश्य मिलता है। बहनों द्वारा भाईयों की कलाई पर बांधी गई राखी के प्रभाव से शास्त्रों में अनेक जगहों पर रक्षाबंधन के महत्व का उल्लेख मिलता है। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि देवता भी यह पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाते थे। पद्म पुराण, स्कन्ध पुराण और श्रीमद्भागवत में वामनावतार नामक कथा में रक्षाबंधन का प्रसंग मिलता है। एक अन्य प्रसंग में जब देवराज इन्द्र बार-बार राक्षसों से परास्त होते रहे और हर बार राक्षसों के हाथों देवताओं की हार से निराश हो गए तो इन्द्राणी ने कठिन तपस्या कर अपने तपोबल से एक रक्षासूत्र तैयार किया। यह रक्षासूत्र इन्द्राणी ने देवराज इन्द्र की कलाई पर बांधा और इस रक्षासूत्र के प्रभाव से देवराज इन्द्र राक्षसों को परास्त करने में सफल हुए। कहते हैं कि तभी से रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत हुई। एक उल्लेख यह भी मिलता है कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था, तब उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर अपनी दानशील प्रवृत्ति के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध राजा बलि से तीन पग भूमि दान में मांगी और बलि द्वारा उनकी मांग स्वीकार कर लिए जाने पर भगवान वामन ने अपने पग से सम्पूर्ण पृथ्वी को नापते हुए बलि को पाताल लोक भेज दिया। कहा जाता है कि उसी की याद में रक्षाबंधन पर्व मनाया गया।

महाभारत काल के एक प्रसंग के अनुसार एक बार भगवान श्रीकृष्ण की उंगली से रक्त बह रहा था। जैसे ही द्रोपदी की नजर गई, उसने तुरंत अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया, जिसके बाद श्रीकृष्ण ने उसकी रक्षा करने का संकल्प लिया, जिसे वे आजीवन निभाते रहे। ऐतिहासिक दृष्टि से इस पर्व की शुरुआत मध्यकालीन युग से मानी जाती है। भारतीय इतिहास ऐसे प्रसंगों से भरा पड़ा है, जब राजपूत योद्धा अपनी जान की बाजी लगाकर युद्ध के मैदान में जाते थे तो उनके प्रदेश की बेटियां उनकी आरती उतारकर उनकी कलाई पर रक्षा-सूत्र बांधा करती थी। बंगाल विभाजन के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता रवीन्द्रनाथ टैगोर ने हिन्दुओं और मुसलमानों से एकजुट होने का आग्रह किया था और दोनों समुदायों से एक-दूसरे की कलाई पर रक्षा-सूत्र बांधने का निवेदन किया था। वास्तव में भाई-बहन के स्नेह, अपनत्व और प्यार के धागों से जुड़ा धार्मिक एवं अलौकिक महत्व का यह पर्व बेहद शालीन एवं सात्विक संबंधों का पावन त्योहार है। कलाई पर बांधे जाने वाले कच्चे धागों से पक्के रिश्ते बनते हैं। भारत के हर सम्प्रदाय में भाई-बहन के रिश्ते को पवित्रता की नजर से देखा गया है और रक्षाबंधन का पर्व आत्मीयता और स्नेह के बंधन से रिश्तों को मजबूती प्रदान करने का पावन पर्व है। श्रावण मास की अंतिम तिथि वाली श्रवण नक्षत्रयुक्त पूर्णिमा को श्रावणी कहते हैं और इस दिन रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है।

(लेखिका स्तंभकार व शिक्षक हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

राम सब घट मेरा साइयां

संकलित
दर्शन

पूरे संसार में राम का निवास है, सबमें भगवान हैं और हम उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। राम ईश्वर के रूप में सबके हृदय में है। कबीर ने कहा है-'राम सब घट मेरा साइयां'... राम ईश्वर के रूप में सबके हृदय में हैं। सदा सर्वदा सबके हृदय में रहेंगे, लेकिन हमारे स्वार्थ, हमारे हेतु, हमारी मानसिकताओं के कारण कभी-कभी हम राम को साधन बना बैठते हैं। इसलिए हम राम को सही रूप में नहीं समझ पाते। प्रत्येक व्यक्ति में यदि हमें सिया राम के दर्शन होने लगें तो तमाम भेदभाव समाप्त हो जाएंगे। जातीय आधार पर भेदभाव काफी हद तक कम हुआ है, लेकिन अब भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। इसके लिए धर्माचार्यों को आगे आना होगा। धार्मिक क्षेत्र हो, राजनीतिक या फिर सामाजिक क्षेत्र, अंतिम व्यक्ति पूज्य होना चाहिए। अगर अंतिम व्यक्ति आप तक नहीं पहुंच पा रहा है तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस तक पहुंचें। भारतीय दर्शन में इहलोक और परलोक की बात आती है। इहलोक और परलोक का कल्याण करने की बात मेरी दृष्टि में इह यानी अपने संसार के साथ-साथ दूसरों का भी कल्याण हो, ऐसा प्रयास करना ही इहलोक और परलोक को सुधारना है। दूसरों के कल्याण की भावना का क्षेत्र बहुत व्यापक है। हम व्यापक व विराट की संतान हैं, इसलिए दूसरों के कल्याण का भारतीय सोच पूरे विश्व के कल्याण का सोच है। जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो दुनिया के सभी देशों के कल्याण की बात करते हैं।

तुलसीदास जी द्वारा विप्रचंद ब्राह्मण पर कृपा

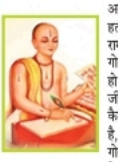

संकलित
प्रेरणा

एक बार एक विप्रचंद नामक ब्राह्मण से हत्या हो गयी और उस हत्या के प्रायश्चित के लिये वह अनेक तीर्थों में घूमता हुआ काशी आया। वह मुख से पुकार कर कहता था: राम राम ! मै हत्यारा हूँ, मुझे भिक्षा दीजिये। श्री गोस्वामी जी ने उसके मुख से अपने इष्टदेव का अतिसुंदर राम नाम सुनकर उसे अपने निवास स्थान पर बुला लिया और उसे हृदय से लगा लिया। गोस्वामी जी ने बड़ी प्रसन्नता से उसे अपनी पंक्ति में बैठकर प्रसाद खिलाया जिससे वह शुद्ध हो गया। काशी के ब्राह्मणों ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने एक सभा की और उसमें गोस्वामी जी को बुलवाया। सभी पंडितो ने गोस्वामी जी से पूछा कि प्रायश्चित पूरा हुए बिना ये ब्राह्मण कैसे शुद्ध हो गया? गोस्वामी जी ने कहा कि वेदों पुराणों में भगवान के नाम की महिमा लिखी है, उसे पढ़कर देख लीजिये। भगवननाम के प्रताप से ही यह ब्राह्मण भी शुद्ध हो गया। उन्होंने गोस्वामी जी से कहा कि महिमा लिखी तो है परंतु हमें विश्वास नहीं होता। गोस्वामी जी ने पूछा कि फिर आपको कैसे होगा विश्वास वह उपाय कहिये? इस पर ब्राह्मणों ने कहा: यदि इस व्यक्ति के हाथ से भगवान शंकर के नंदी जी प्रसाद खा लें तो हम लोग इसे अपनी जाति, पंगति में ले सकते हैं अथवा नहीं। सब लोग काशी में ज्ञानवापी नदी के तट पर पहुंचे जहां शर्त रखी गयी थी। श्री गोस्वामी जी ने नन्दीश्वर से कहा: हे नंदीश्वर ! यदि यह ब्राह्मण राम नाम के प्रताप से शुद्ध हो गया है तो आप इसके हाथ से प्रसाद स्वीकार करके नाम की महिमा को प्रमाणित कीजिये। नन्दीश्वर ने प्रसन्नता के साथ प्रसाद स्वीकार कर लिया।

अंतर्मन

आज की पाती

देश खुशहाल तो हम खुशहाल

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित करते हुए कहा कि कलह पैदा करने वाली प्रवृत्तियों को समाज को खारिज करना चाहिए। राष्ट्रपति ने देश और समाज के कल्याण के लिए बहुत बढ़िया सलाह हमें दी, लेकिन अफसोस कि बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो इस पर अमल करेंगे, बाकियों को तो अपने स्वार्थ से ही फुर्सत नहीं। ऐसे लोग देश और समाज के बारे में क्या सोचेंगे? अगर हम धर्म और जाति के जंजाल में ही उलझे रहेंगे और इन भावनाओं में बहकर देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश किसी न किसी तरह करते रहेंगे तो हमारे देश और समाज कभी भी बुलंदियों से आजाद नहीं हो पाएगा। इसके विपरीत हम अपना ही नहीं, बल्कि अपनी भावी पीढ़ी का भविष्य भी दांव पर लगा देंगे। हमें यह बात समझनी है कि देश की खुशहाली में ही सबकी खुशहाली है। *- तपन चक्रवर्ती, महासमुंद*

टेंड

नागरिकता पाएं

आज भी कुछ राज्य सरकारें हैं जो लोगों को गुलाम कर रही हैं। मैं आज देशभर के तहसीलों बहनों-भाइयों को कहता हूँ कि, आप बेईझिक छत्तीसगढ़ टीजिए और नागरिकता प्राप्त कीजिए।
-अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

कानून अपनाने को कहा था

देशभर के डॉक्टर अपने खिलाफ हिंसा का विरोध करते हुए हड़ताल पर हैं, यह संसद ने मेरे हस्तक्षेप वाले बार दिलाता है जिसने सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए एक कानून अपनाने को कहा था। मेरे निजी सदस्य के विधेयक को खारिज कर दिया गया। -सांसद थरूर, कांग्रेस नेता

पुष्पा द्रविड़ की पेंटिंग्स

एलजीसाइ ने पुष्पा द्रविड़ की पेंटिंग्स की प्रदर्शनी प्रदर्शनी को देखने का सौभाग्य मिला। यह एक ऐसी प्रतिभाशाली कलाकार है, जिन्होंने अमूर्त से लेकर आलंकारिक और वहां तक कि मिथिलिपि तक विभिन्न कला रूपों के साथ प्रयोग किया है।
-किरण मजूमदार-शॉ, उद्यमी

क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा

महान क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने मात्र 25 साल की आयु में खुद को देश के लिए बलिदान कर दिया था। उस अमर बलिदानी के त्याग और समर्पण को क्या हम आजाद भारत में उचित सम्मान दे पाए?
-राज बब्बर, पूर्व सांसद व अभिनेता

करंट अफेयर

ट्रंप का हैरिस पर हमला बेहतर दिखने का दावा

राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रतिद्वंद्वी डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस के खिलाफ निजी हमला करते हुए कहा कि वह 'उनसे कहीं ज्यादा अच्छे दिखते हैं।'

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को पेंसिल्वेनिया में एक रैली में यह टिप्पणी की। ट्रंप ने 'ट्रुथ' पत्रिका के हालिया आवरण पृष्ठ का हवाला दिया, जिसमें उपराष्ट्रपति हैरिस को दिखाया गया है। ट्रंप (78) ने 'ट्रुथ' पत्रिका के चित्रकार द्वारा हैरिस (78) के चित्र के साथ 'अत्यधिक उदारता'' दिखाने की आलोचना करते हुए कहा, 'मैं उनसे कहीं अधिक अच्छा दिखता हूं।' ट्रंप पिछली रैलियों में भी इस तरह की टिप्पणियां कर चुके हैं।पूर्व राष्ट्रपति ने कहा, 'ट्रुथ पत्रिका के पास उनकी (हैरिस) कोई तस्वीर नहीं है। उनके पास एक अविश्वसनीय कलाकार है जो उनके चित्र बना रहा है। उन्होंने बहुत सारी तस्वीरें लीं जो काम नहीं आईं, इसलिए उन्होंने स्केच कलाकार को काम पर रखा।' ट्रंप ने उपराष्ट्रपति हैरिस पर उनकी आर्थिक नीति को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने पिछले सप्ताह कहा था कि उन्हें हैरिस पर व्यक्तिगत रूप से हमला करने का 'अधिकार' है, क्योंकि वह 'उनके प्रति बहुत सम्मान नहीं रखते।''

ऑफ बीट

मृदा से आती ध्वनियां देती हैं मृदा की सेहत की जानकारी

अच्छी मृदा का सीधा संबंध जीवन से है। पृथ्वी की 59 प्रतिशत प्रजातियां मृदा में ही रहती हैं। वे मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और अगर व्यापक रूप से बात करें तो ये प्रजातियां धरती की सेहत को भी दुरुस्त बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण संसाधन खतरे में है। वर्तमान में दुनिया की 75 प्रतिशत मृदा की गुणवत्ता खराब है। वनों की कटाई, पशुओं के अत्यधिक चरने, शहरीकरण और अन्य क्रियाकलापों के कारण यह आंकड़ा 2050 तक 90 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।

मृदा की गुणवत्ता में गिरावट न केवल जैव विविधता के लिए, बल्कि फसल उत्पादन जैसे कामों के लिए भी बड़ा जोखिम पैदा करती है। मिट्टी में जीवन का पता लगाने और मापने के पारंपरिक तरीके अक्सर महंगे, समय लेने वाले होते हैं। इकोअकाउस्टिक्स' एक नवीन और गैर-विनाशकारी पहल है जो मृदा गुणवत्ता की निगरानी के तरीके को बदल सकती है। हमारी शोध टीम ने ध्वनि के इस्तेमाल से मिट्टी में जीवन की निगरानी का एक सरल तरीका विकसित किया है। यह तकनीक दुनिया भर में मृदा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

जब महिलाएं रात में स्वतंत्र होकर सड़कों पर निकल सकेंगी, तभी सही मायनों में भारत स्वतंत्र होगा। -महात्मा गांधी

कर्नाटक के राज्यपाल ने मुडा घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है, जो राज्य सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन अगर आरोप लगे हैं, तो व्यवस्थित जांच के जरिये सच सामने आना ही चाहिए।

शुचिता का सवाल

कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाने की अनुमति देने से राज्य की पंद्रह माह पुरानी कांग्रेस सरकार को जोरदार झटका तो लगा ही है, इससे कर्नाटक की राजनीति में एक नया मोड़ भी आया है, जिसके प्रभाव दूरगामी हो सकते हैं। दरअसल, शिकायतकर्ताओं की याचिका पर जवाब देने के लिए राज्यपाल द्वारा 26 जुलाई को मुख्यमंत्री को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था, जिस पर राज्य सरकार ने उन्हें नोटिस वापस लेने और याचिका खारिज करने का परामर्श दिया था। लेकिन राज्यपाल ने इस परामर्श को अतार्किक मानते हुए मामले की तटस्थ, वस्तुनिष्ठ और गैर-पक्षपातपूर्ण जांच को जरूरी बताया, जिससे आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। गौरतलब है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस), दोनों के तहत किसी मुख्यमंत्री या मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जांच या मुकदमा चलाने की स्वीकृति देने के लिए सक्षम अधिकारी राज्यपाल ही है। नहीं भूलना चाहिए कि 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ जब राज्यपाल ने अभियोजन की स्वीकृति दी थी, तब सिद्धरमैया ने कहा था कि येदियुरप्पा को एक मिनट के लिए भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। अब भाजपा स्वाभाविक ही पलटवार करते हुए उनसे इस्तीफे की मांग कर रही है। कहा जा रहा है कि यह घोटाला चार से पांच हजार करोड़ रुपये मूल्य का भी हो सकता है। कथित आरोप है कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती के पास मैसूरू जिले में तीन एकड़ से ज्यादा जमीन थी, जिसे मुडा ने विकास के लिए लिया और मुआवजे के तौर पर उन्हें मैसूरू के महंगे इलाके में जमीन दी गई, जिसका मूल्य उस जमीन की तुलना में काफी ज्यादा था, जिसे मुडा ने अधिगृहीत किया था। वर्ष 1998 से लेकर अब तक सिद्धरमैया कर्नाटक की राजनीति में प्रभावशाली रहे हैं। मुमकिन है, वह सीधे तौर पर इन घोटालों से न जुड़े हों, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर करीबियों को कथित फायदा पहुंचाया। ये आरोप निस्संदेह सिद्धरमैया की छवि पर आघात पहुंचाने वाले हैं। मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल द्वारा दी गई मंजूरी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। सिद्धरमैया बेशक इसे राज्य को अस्थिर करने की चाल बताएं, पर इससे उनकी बेगुनाही साबित नहीं होती। अगर आरोप निराधार हैं, तो हर कोई चाहेगा कि सिद्धरमैया भी बेदाग होकर निकलें, लेकिन इसके लिए उन्हें जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं से तो गुजरना ही होगा।

महिलाओं को कब मिलेगी डर से आजादी

कोलकाता इन दिनों 31 वर्षीय एक पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की वजह से सुर्खियों में हैं। वहां हजारों लोगों ने स्वतंत्रता और बिना किसी डर के जीने की आजादी की मांग करते हुए मार्च किया। आखिर महिलाओं को सुरक्षा मांगने की जरूरत क्यों पड़ती है?

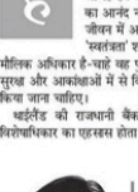

पत्रलेखा चटर्जी
वरिष्ठ पत्रकार

हमारे पास वर्ग करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमें उन मुट्ठी पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, जो पीछे ले जा रहे हैं। जब लाखों भारतीय महिलाएं भय से मुक्ति का आनंद नहीं ले पाती हैं, जब वे अपने रोजमर्रा के जीवन में असुरक्षित महसूस करती हैं, तो उनके लिए 'स्वतंत्रता' शब्द का क्या अर्थ है? सुरक्षा हर इन्सान का मौलिक अधिकार है-चाहे वह पुरुष हो या महिला। किसी भी महिला को सुरक्षा और आकांक्षाओं में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में, जहां मैं अभी हूं, मुझे अपने विशेषाधिकार का एहसास होता है। मैं बिना किसी डर के अकेले सड़कों पर चलती हूं, देर रात सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करती हूं। मैं थाई नहीं बोलती, लेकिन जब भी मैं बाहर जाती हूं, तो पीछे मुड़कर नहीं देखती हूं कि कौन मेरा पीछा कर रहा है, चाहे मैं अकेले होऊं या देर रात हो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस शहर में एक संपन्न सड़क अर्थव्यवस्था है; सड़कों पर कई अकेली महिलाएं विभिन्न तरह के उत्पाद बेचती हैं, जो देर रात तक काम करती हैं। वे अकेले सड़क पर चलने से नहीं डरतीं। यह एक आदर्श स्थिति है और दुनिया के हर शहर में ऐसा ही होना चाहिए।

कोलकाता, जहां मेरा जन्म हुआ और जहां मैं पली-बढ़ी, इन दिनों आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की एक 31 वर्षीय पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल छात्रा के साथ बीते नौ अगस्त को हुए भयानक दुष्कर्म और हत्या की वजह से सुर्खियों में है। इस घटना ने कोलकाता शहर और पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। देश भर में डॉक्टरों, मेडिकल छात्रों और नागरिक समाज द्वारा व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ है। चिकित्सा बिरादरी, विशेष रूप से महिला डॉक्टरों का कहना है कि उनकी लड़ाई सुरक्षा के खतरों, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, अपर्याप्त सुरक्षा और महिलाओं की अस्मत से खिलवाड़ करने वाले चरित्रों के खिलाफ है।

दुष्कर्म का शिकार हुई मेडिकल छात्रा (जूनियर डॉक्टर) ने लगातार 36 घंटे की पाली में काम किया था और वह थोड़ा आराम करना चाहती थी। लेकिन वहां इसके लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। इसलिए वह खाली पड़े सेमिनार हॉल में जाकर सो गई। उसके बाद जो हुआ, वह एक भयावह कहानी है, जिसके बारे में हाल में अखबारों के पहले पन्ने पर छपा है। इस घटना के बारे में बहुत से तथ्य ऐसे हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते। लेकिन हम जो जानते हैं, वह जवाबदेही की भारी कमी की ओर इशारा करता है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल के कामकाज को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिन्होंने विरोध प्रदर्शनों के बीच इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वह अब भी जवाबदेह हैं। स्थानीय पुलिस और राज्य सरकार से भी जायज सवाल पूछे जा रहे हैं।

दुष्कर्म और हत्या के विवरण ऐसे कई मुद्दों को उजागर करते हैं, जिन पर तत्काल प्रतिक्रिया की आवश्यकता है, न कि त्वरित समाधान की। इनमें से कई मुद्दे चिकित्सा समुदाय से जुड़े हैं। ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टरों के आराम के लिए सुरक्षित जगह की कमी, जो इस घटना का मूल कारण है, केवल कोलकाता या पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है। केंद्र संचालित डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 2001 में काम कर चुकी एक महिला डॉक्टर ने बताया, 'दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में कोई ड्यूटी रूम नहीं था। हम सीमेंसयू (कार्डियक केयर यूनिट) में दो कुर्सियों पर सोते थे।' ऐसे कई अन्य प्रश्न हैं, जो आम भारतीय महिलाओं के दैनिक जीवन में सुरक्षा को प्रभावित करते हैं, चाहे ये कुछ भी कर रही हों या कहीं भी हों। कोलकाता और उसके उपनगरों में हजारों लोगों ने 'रिक्लेम द नाइट' मार्च में हिस्सा लिया और 'स्वतंत्रता और बिना किसी डर के जीने की आजादी' की मांग की। यह एक बुनियादी जरूरत है। हजारों लोगों ने सरकारी अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की निंदा की और महिलाओं की बेहतर सुरक्षा के लिए प्रदर्शन किया। आखिर महिलाओं को सुरक्षा मांगने की जरूरत क्यों पड़ती है? भारतीय संविधान, खासकर अनुच्छेद 14 और 21 महिलाओं को भी मौलिक और समान अधिकारों की गारंटी देता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है।

शर्मनाक बात यह है कि देश में ज्यादातर जगहों पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जब सड़कों, सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर महिला सुरक्षा की बात आती है, तो कोई भी राजनीतिक दल इस मामले पर कुछ नहीं बोलता। बहुत-सी महिलाएं तो अपने घर की चहारदिवारी में भी सुरक्षित नहीं हैं। लाखों भारतीय महिलाओं को अब भी चुप रहने के लिए कहा जाता है और पीड़िता को ही दोषी ठहराया जाता है, जिससे यौन शोषण की शिकार बची हुई महिलाओं के लिए कानूनी और सामाजिक सहायता प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है।

कोलकाता में हुई दुष्कर्म की घटना 2012 में दिल्ली में 23 वर्षीय छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या से मिलती-जुलती है, जिसके बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए थे और भारत में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठे थे। बलात्कारियों और हत्यारों को मौत की सजा देने के प्रावधान से भी महिलाओं को कोई राहत नहीं मिली है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अकेले 2022 में 31,516 दुष्कर्म के मामले दर्ज किए। राजस्थान में सबसे ज्यादा 5,399 मामले दर्ज किए गए, उसके बाद उत्तर प्रदेश (3,690) और मध्य प्रदेश (3,029) का स्थान रहा। ये सिर्फ दर्ज मामले हैं, वास्तविक आंकड़े तो कहीं ज्यादा होंगे। अब एक बार फिर दोषियों को मौत की सजा देने की बात हो रही है। लेकिन इससे महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी। जरूरत है, पारदर्शिता और जवाबदेही की। भारत में महिलाओं को हमेशा सतर्क रहने की आदत हो गई है। इसका महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और उनकी आकांक्षाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक दलों को संकीर्णता से ऊपर उठकर इसे राष्ट्रीय मुद्दा मानना चाहिए। खानी राजनीतिक दलों को कुछ बलात्कारियों को बचाने और अन्य के खिलाफ मुखर होने की प्रवृत्ति नहीं अपनानी चाहिए। जनता उनके पाखंड को देख रही है।

भारत अगले तीन वर्षों में 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना चाहता है। एक कामकाजी महिला और एक मां होने के नाते मेरी राजनेताओं और प्रशासकों से अनुरोध है कि वे सबसे पहले महिलाओं को सुरक्षा दें। जब महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी, तभी देश तरक्की करेगा।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

माता अमृतानंद

रक्षाबंधन का त्योहार पारिवारिक दायरे का भी विस्तार करता है। अपनों की कलाई पर राखी बांधी जाती है, तो यह सामंजस्यपूर्ण सामाजिक जीवन की जरूरत को रेखांकित करता है।

रक्षा सूत्र वास्तव में प्रेम का बंधन है

रक्षाबंधन पूरे देश में पौराणिक काल से मनाया जाने वाला एक लोकप्रि त्योहार है। रक्षा बंधन की अवधारणा मुख्य रूप से हर प्रकार की सुरक्षा प्रेम पर आधारित है। रक्षा के लिए धागा बंधवाने की परंपरा हमारे देश में विभिन्न अवसरों पर देखी जाती है। आमतौर पर हम देखते हैं कि लोग पूजा के बाद या पूजा के दौरान पुजारी से अक्सर अपने हाथों में पवित्र बंधवाते हैं। वाराणसी के काल भैरव के मंदिर में लोग अपनी कलाई पर धागा बंधवाते हैं। जबकि जम्मू के श्रीवैष्णो देवी मंदिर में भी हम देखते लोग देवी की पूजा करने के बाद अपने माथे पर लाल धागा एवं कपड़ा

हैं। हिंदू धार्मिक समारोहों में आप अक्स देखते होंगे कि पुजारी अनुष्ठान शुरू पहले अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति की पर धागा बांधते हैं।

लोगों के बीच यह आम धारणा है कि सिर्फ भाई-बहनों का ही त्योहार है, ले ऐसा नहीं है। यह एक पत्नी अपने पति एक शिष्य अपने गुरु को भी बांध सक यह बंधन सिर्फ अपने खून के रिश्तेदा सीमित नहीं है, एक लड़की राखी बांध किसी को अपना भाई बना सकती है।

सूत्र वास्तव में प्रेम का बंधन है।

रक्षाबंधन का त्योहार न सिर्फ प्यार के को मजबूत बनाता है, बल्कि पारिवारि दायरों का भी विस्तार करता है। जब दोस्तों और पड़ोसियों की कलाई पर राखी बांधी जाती है, तो यह एक सामंजस्यपूर्ण सामाजिक जीवन की जरूरत को रेखांकित करता है।

यह त्योहार किसी व्यक्ति की दृष्टि को अपने परिवार की सीमाओं से परे धरती को एक परिवार के रूप में मानने के लिए प्रेरित करता है-यह पुरा सौहार्द्र के एक धागे में सभी को पिरोता है और यह वसुधैव कुटुंबकम भारतीय जीवन मूल्य की याद दिलाता है। भारतीय धार्मिक मान्यताओं अ 'भविष्य पुराण' के अनुसार, देवों के राजा इंद्र को देवगुरु बृहस्पति ने श सुरक्षा के लिए राखी पहनने की सलाह दी थी, जब वह युद्ध में वृत्रासुर पिछड़ रहे थे। उस समय इंद्र की पत्नी शची ने इंद्र को राखी बांधी थी। अन्य पौराणिक कथा के अनुसार, राखी के त्योहार को समुद्र देवता वरु पूजा से जोड़ा जाता है और आमतौर पर मछुआरे समुद्र देवता को नारि राखी चढ़ाते हैं। इसलिए इस त्योहार को नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता त्योहार के संबंध में कई ऐतिहासिक संदर्भ भी हैं। रक्षाबंधन का त्योहार देखभाल, प्रेम, सम्मान और एक बेजोड़ बंधन का प्रतीक है। लेकिन रक्ष को व्यापक परिप्रेक्ष्य से देखें, तो इस त्योहार में सार्वभौमिक भाईचारे औ बहनापे का एक अंतर्निहित संदेश है। राखी के त्योहार का सामाजिक औ आध्यात्मिक का महत्व है, जो सकारात्मक गुणों के पोषण, विचार, वच कर्म में शुद्धता की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

परस्पर भरोसा बनाए रखें

सूत्र

जब तक हम सामाजिक जीवन में प्रेम और विश्वास को बनाए नहीं रखेंगे, तब तक कोई हम पर भरोसा नहीं कर पाएगा। अपने आत्मीय लोगों का भरोसा जीतना और परस्पर प्रेम बनाए रखना जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूर होता है। पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मान लेने हमारा कोई शत्रु नहीं होता है।

दूसरा पहलू

वर्ष 1972 में जिस व्हेल की तस्वीर ली गई थी, उसे पिछले महीने अलास्का के पास प्रशांत महासागर में देखा गया।

दुनिया की सबसे पुरानी व्हेल कैसे बच गई

हंपबैक व्हेल की पूंछ फिंगरप्रिंट की तरह अनोखी होती है। उसकी पूंछ का हिस्सा कंगूरेदार होता है, जो हर व्हेल में अलग-अलग होता है। निचली सतह पर अलग-अलग काले और सफेद पैटर्न होते हैं, जो जीवन भर उसकी पहचान करते हैं। जुलाई में जब हिले शिप हवाई विश्वविद्यालय के एक समुद्री शोधकर्ता एडम ए पैक अलास्का के फ्रेडरिक साउंड में व्हेल की तस्वीर ले रहे थे, तभी उन्होंने एक पुरानी व्हेल को पहचान लिया था। उन्होंने पाया कि ज्यादातर काली और किनारे के पास सफेद धब्बे वाली यह पूंछ ओल्ड टाइमर नामक व्हेल की है, जिसे पहली बार 1972 में देखा गया, जो अब करीब 53 वर्ष की है।

एमिली एंथेस

डॉ. पैक ओल्ड टाइमर को लेकर चिंतित थी, जब उन्होंने अप्रैल मार्च 2015 में प्रचंड गर्मी के बीच उसे देखा था। नौ वर्ष बाद ओल्ड टाइमर ओपिन पाई गई।

डॉल्फिन इंस्टीट्यूट के सह-संस्थापक और अध्यक्ष डॉ. पैक कहते हैं कि ओल्ड टाइमर दुनिया के ज्ञात हंपबैक व्हेल में सबसे पुरानी है। हंपबैक व्हेल की आबादी एक समय व्यावसायिक शिकार की वजह से काफी कम हो गई थी, जो हाल के दशकों में फिर से बढ़ी है। लेकिन जहाजों से टकराने और जलवायु परिवर्तन से उन्हें अब भी खतरा है। डॉ. पैक ओल्ड टाइमर को लेकर चिंतित थे, जब उन्होंने आखिरी बार 2015 में प्रचंड गर्मी के बीच उसे देखा था। हंपबैक व्हेल समेत सैकड़ों पक्षी और समुद्री स्तनधारी उस गर्मी में मर गए थे। ऐतिहासिक रूप से व्हेल के ठिकानों का पता लगाना कठिन है-वैज्ञानिक नई तस्वीरों की तुलना पुरानी तस्वीरों से करते हैं। लेकिन ओल्ड टाइमर और अन्य हंपबैक के भाग्यी अध्ययन फ्लिप बुडिमशा (एआई) से किए जाने की तैयारी चल रही है। डॉ. पैक को उम्मीद है कि इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलेगी कि कैसे और क्यों कुछ व्हेल कठिन परिस्थितियों का सामना कर पाती हैं।

उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में हंपबैक की बड़ी आबादी है। हंपबैक व्हेल वैज्ञानिकों के लिए सतत अध्ययन का विषय रही हैं, जो 1976 में शुरू हुआ था, जब एक समुद्री स्तनपायी जीवों के शोधकर्ता लुई हरमन ने व्हेल और उनके विशिष्ट फ्लुक की तस्वीरें लेनी शुरू की थीं। डॉ. हरमन के पास करीब तीस हजार से अधिक तस्वीरें हैं, जिससे व्हेल के जीवन, उनके प्रवास पैटर्न से लेकर उनके सामाजिक व्यवहार तक के बारे में नई जानकारी मिली है। बहरहाल डॉ. पैक पता लगा रहे हैं कि आखिर ओल्ड टाइमर कैसे बच गया? अब अध्ययन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैम्पबैल की मदद से मशीन लर्निंग के युग में प्रवेश कर रहा है।

©The New York Times 2024

आंकड़े

रहने योग्य शहर

जीवन की सुगमता सूचकांक (2024) के अनुसार, हमारे देश में बंगलूरू रहने के लिए सबसे उत्तम शहर है।

आंकड़े रहरहें के स्कोर के हैं। | चार्ट : EIU

आज श्रावण मास की पूर्णिमा है, आज के ही दिन द्रौपदी ने अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर भगवान श्रीकृष्ण की उंगली पर बांधा था।

द्रौपदी ने बांधा श्रीकृष्ण को रक्षा सूत्र

अंतर्यात्रा
संकलित

भगवान श्रीकृष्ण ने शिशुपाल को उसकी सौ गलतियों को माफ करने का वचन दिया था। लेकिन शिशुपाल आगे भी गलतियां करने से बाज नहीं आया। भगवान श्रीकृष्ण ने शिशुपाल की 100 गलतियां तो माफ कर दीं, लेकिन 101वीं गलती पर अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया।

सुदर्शन चक्र चलाने की वजह से उनकी उंगली से रक्त की धारा बहने लगी। यह दृश्य देखकर द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर भगवान श्रीकृष्ण की उंगली पर बांध दिया। इस पर कृष्ण ने कहा, 'बहन, तुम्हारा यह चीर मुझ पर ऋण है। अब से तुम्हारी रक्षा करने का दायित्व मेरा है।' संयोगवश यह घटना श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन घटित हुई थी।

पांडव, कौरवों से जुए में सब कुछ हार चुके थे। सब कुछ हारने के बाद शकुनि और दुर्योधन के उकसावे में आकर पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और उन्हें भी हार गए। इसके बाद दुःशासन ने दुर्योधन के कहने पर भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की। अपने चीरहरण के दौरान द्रौपदी ने 'हरि अभयम कृष्णा अभयम' का जाप कर भगवान श्रीकृष्ण को अपनी रक्षा के लिए पुकारा। खुद को पुकारे जाने पर श्रीकृष्ण ने जरा भी विलंब नहीं किया और इस तरह श्रीकृष्ण ने अदृश्य रूप में आकर अपनी बहन द्रौपदी की रक्षा की।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 22 मार्च 19

महिला शिक्षा योजना में सु के लिए विशेष समिति बने

लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान
श्रीमती दुर्गाबाई की अध्यक्षता में सुझाव देने को समिति बनेगी

आज लोकसभा ने मंत्रालय की 37 क रुपये की मांगें पारि दीं। शिक्षा मंत्री डॉ. कालूलाल श्रीमानी घोषणा की कि सरक महिला शिक्षा योज सुधार के लिए एक समिति बनाएगी।

सौवें वर्ष में काकोरी की याद

काकोरी के क्रांतिकारियों ने देश की मुक्ति के साथ सामाजिक सद्भाव की जिस इबारत को अपने बलिदान से रचा, वह आज भी स्मरणीय है।

सुधीर विद्यार्थी | इतिहास

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के असहयोग आंदोलन (1921) को क्रांतिकारियों ने धैर्य के साथ देखा था, लेकिन चौरा-चौरी में हुई हिंसा के बाद उस जनांदोलन को एकाएक रोक दिए जाने से विप्लवकारी ही नहीं, गांधी जी के सहयोगी भी नाराज और निराश हो गए थे। ऐसे में क्रांतिकारियों ने पहली बार अखिल भारतीय स्तर पर 'हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ' (एचआरए) नाम से नए दल का गठन करके उसका संविधान रचा, जिसमें कहा गया था कि वे ऐसे समाज का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसमें एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का और एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण संभव नहीं होगा।

इस दल के 10 नौजवानों ने रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में नौ अगस्त, 1925 को लखनऊ में काकोरी के निकट एक सवारी रेलगाड़ी को रोक कर सरकारी खजाना लूट लिया, जिसमें अशफाकउल्ला खां, मन्मथनाथ गुप्त, कुंदनलाल गुप्त, शचीन्द्रनाथ बख्शी, चंद्रशेखर आजाद, मुकुंदीलाल, मुरारीलाल, केशव चक्रवर्ती और बनवारी लाल शामिल थे। इस घटना से ब्रिटिश सरकार भौंचक्की रह गई। क्रांतिकारियों का ब्रिटानी हुकूमत पर यह सीधा प्रहार था, जो बहुत कारगर सिद्ध हुआ। पकड़े गए क्रांतिकारियों पर लखनऊ में 18 महीने चले इस मुकदमे को देशव्यापी ख्याति मिली, जिसमें बिस्मिल, अशफाकउल्ला और रोशनसिंह को 19 दिसंबर, 1927 को फांसी पर चढ़ा दिया गया, जबकि राजेंद्र लाहिड़ी को अज्ञात कारणों से दो दिन पूर्व ही 17 दिसंबर, 1927 को गोंडा जेल में फांसी दे दी गई।

काकोरी कांड की विशेषता यह थी कि देश की क्रांतिकारी गतिविधियां, जो पहले छोटेमार लड़ाइयों के रूप में जारी थीं, वे एकजुट होकर एक बड़े दल और तीव्र विचारवान अभियान के तौर पर सामने आईं। असल बात यह है कि असहयोग आंदोलन की निराशाजनक समाप्ति के बाद भारतीय राजनीति में जो एक खालीपन आ गया था, उसे भरने में इस क्रांतिकारी कार्रवाई ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

इस घटना ने देश का ध्यान सांप्रदायिकता से स्वतंत्रता संग्राम की ओर भी मोड़ा। काकोरी शहीदों का बलिदान देश की सर्वाधिक रोमांचकारी घटना बनी और इस संघर्ष में अशफाकउल्ला की उपस्थिति और सक्रियता ने उसे ऐसे साझे संघर्ष और साझी शहादत का दर्जा दे दिया, जो पूर्व में दुर्लभ था।

बिस्मिल और अशफाक भिन्न धार्मिक आस्थाओं के होते हुए देश की आजादी के लिए साझे मार्ग के राही बने। उन्होंने स्वतंत्रता-प्राप्ति के रास्ते में धर्म को बाधक नहीं बनने दिया। अशफाक अपने क्रांतिकारी जीवन में निरंतर दृढ़तर होते चले गए। मुकदमे के दौरान उन्हें माफ करने और विदेश भेजने का लालच भी दिया गया, पर वह डिगे नहीं। अशफाक ने किसानों और मजदूरों की ताकत को पहचाना और पहली बार कम्युनिस्ट सिद्धांतों की वकालत की।

बिस्मिल ने भी अंतिम दिनों में नौजवानों से अपने संदेश में कहा था कि वे रिवॉल्वर या पिस्तौल त्याग कर वास्तविक साम्यवादी बनने का प्रय फांसी से दो दिन पहले तक गोरखपुर ज कालकोठरी में लिखी गई बिस्मिल की आत्म जीवनी-साहित्य का अमूल्य दस्तावेज होने क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास के उस काल निष्पक्ष मूल्यांकन भी है, जिसमें वह स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने के लिए हथियार ही नहीं, बल्कि और साहित्य को एक जरूरी माध्यम समझने बिस्मिल स्वयं कलम के बहुत धनी थे। अप काल में उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों अनेक पुस्तकों की रचना की।

अपने जीवन के अंतिम दौर में बिस्मिल ने लगा था कि अभी जनता क्रांतिकारी संघर्ष समर्थन नहीं दे रही है, जितना अपेक्षित बिस्मिल का निराशावाद नहीं है, बल्कि क्रां वैचारिक चेतना के निर्माण के लिए की ज जरूरी कार्यवाई की जरूरत थी।

काकोरी केस में पकड़े गए क्रांतिकारी स्वरूप सेठ और राजेंद्र लाहिड़ी जेल से अदा समय 'भारतीय प्रजातंत्र की जय' के नारे ल जबकि कांग्रेस बहुत आगे चलकर भी 'पूर्ण स्व की लक्षित नहीं कर पाई थी। काकोरी की घ बाद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दल के के समय भगत सिंह के सुझाव पर पार्टी के 'समाजवादी' शब्द जोड़कर उन्होंने पार्टी और भी स्पष्ट कर दिया था। एक शताब्दी पूर्व के क्रांतिकारियों ने देश की मुक्ति के साथ स सद्भाव की जिस इबारत को अपने बलिदान वह आज भी स्मरणीय है।

100 किलोमीटर के करीब का हिस्सा ऐसा है भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जिसकी व्यवस्थित बाड़बंदी नहीं हो पाई है। यह चुनौती की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है।

डा. संजय वर्मा
असिस्टेंट प्रोफेसर, बेनेट यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा

आजकल

पलायन की त्रासदी से त्रस्त बांग्लादेशी हिंदू

मानव सभ्यता के इतिहास में सबसे अधिक आपदाएं पलायन की घटनाओं के हिस्से आती हैं। वस्तुत: संघर्ष, भुखमरी, बेरोजगारी, आर्थिक बदहाली जैसे विभिन्न कारणों से होने वाली ये घटनाएं विश्व के विभिन्न समुदायों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करने के लिए मजबूर करती हैं। ऐसे में बांग्लादेश के एक राष्ट्र के रूप में गठन से पहले से ही उस भूभाग से जिस प्रकार से हिंदू जनसंख्या को भारत की ओर जबरन पलायन करना पड़ रहा है, वह हमारे लिए भी त्रासदपूर्ण घटना है, लिहाजा इस बारे में हमें गंभीरता से विचार करना होगा

बंग्लादेश में दमन एवं उत्पीड़न के शिकार हिंदू भारतीय सीमा में प्रवेश के लिए प्रयास करते हुए। फाइल

मानव सभ्यता के इतिहास में पलायन की घटना को जीवन के एक हिस्से के रूप में समझा जाता रहा है। वैसे कहा जाता है कि दुनिया को पहले से बेहतर बनाने में मानव पलायन की एक बड़ी भूमिका है। आर्थिक और वैज्ञानिक विकास की जिन गाथाओं का श्रेय यूरोप और अमेरिकी देश लेते हैं, दावा है कि उनमें सबसे ज्यादा योगदान उन आप्रवासियों का है जो दुनिया भर से उजड़कर अच्छे जीवन और रोजगार की कामना के साथ वहां पहुंचे। लेकिन जबरिया मानव पलायन का एक पहलू ऐसा भी है, जिसमें हजारों-लाखों इंसानों को कई बार अप्रत्याशित स्थितियों में पड़ोसी देशों समेत दुनिया में जहां ठौर मिलने की संभावना हो, उन देशों की ओर कूच करने और वहां शरण लेने को मजबूर करती है। कुछ ऐसे ही हालात इन दिनों बांग्लादेश में बने हुए हैं। जबरिया पलायन के हालात में वहां से हजारों-लाखों हिंदू भारत से लगती सीमाओं पर इन दिनों डेरा डाले हुए हैं। इन लोगों की मजबूरी भारत के लिए एक मुश्किल स्थिति पैदा कर रही है। ऐसे में कई सवाल और आशंकाएं पैदा हो गई हैं जिनके हल आज जरूरी प्रतीत हो रहे हैं।

मनापलायन के बाद बढ़े हिंदुओं पर हमले : हाल में बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के अपदस्थ होने के बाद वहां के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोगों पर हमले बढ़े हैं। दावा है कि हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर वहां इन दिनों 200 से ज्यादा हिंसक हमले हुए हैं। इन हमलों का कारण यह है कि हिंदू और अल्पसंख्यक आबादी को शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी का समर्थक माना जाता है। हालांकि अंतरिम सरकार के नए प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा देने की अपील की है, लेकिन पुलिस व्यवस्था के चरमराने के कारण हिंदुओं में असुरक्षा का भाव घर कर गया है। ऐसे में ज्यादातर हिंदू आबादी बांग्लादेश से जबरन पलायन को विवश है। हाल में सैकड़ों हिंदू जान बचाकर सरहद पार करने के लिए भारतीय सीमाओं पर जमा हो गए थे। उन्हें सीमा पार करने से रोकने के लिए बार्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) की मानव श्रृंखला बनाने जैसे प्रबंध करने पड़े।

चार हजार किमी सरहद की चुनौती : भारत के जिन पांच राज्यों से बांग्लादेश की 4096 किमी लंबी सरहद जुड़ी हुई है, उनमें बंगाल, त्रिपुरा, असम, मिजोरम और मणिपुर की अधिकांश सीमाओं पर बीएसएफ की यूनिटों में हाई अलर्ट जारी किया जा चुका है। कुछ इलाके या कहें कि सरहदी कस्बे ऐसे हैं, जो भाग-बांग्लादेश में आधे-आधे बंटे हुए हैं। मिसाल के तौर पर बंगाल के जलपाईगुड़ी का फूलबाड़ी-हल्दीबाड़ी कस्बा। दोनों देशों में आधा-आधा बंटा हुआ यह कस्बा बांग्लादेश से भारत आने वालों के लिए सबसे व्यस्त मार्ग उपलब्ध कराता है। सामान्य हालात में यहां से कारोबार के लिए ट्रकों की आवाजाही होती है। लेकिन हाल की बदली स्थितियों में बांग्लादेशी हिंदुओं को यह सबसे सुगम एंट्री प्वाइंट लग रहा है। यहां महानंदा नदी सीमा है। इसके लगभग सौ किलोमीटर हिस्से में बाड़ नहीं है। लोग यहीं से घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। भारत के लिए मुश्किल यह है कि फूलबाड़ी-हल्दीबाड़ी कस्बे में रहने वाले भारतीय परिवारों के तमाम रिश्तेदार बांग्लादेश में पड़ने वाले कस्बे में रहते हैं। हाल में हुए तख्तापलट के बाद जब उनके बांग्लादेशी रिश्तेदारों ने अपने भारतीय परिवारों में शरण लेनी चाही, तो वे ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि वहां तैनात बीएसएफ जवानों को ऐसी किसी भी आमद को रोकने के निर्देश हैं।

समुद्री सीमा पर भी हलचल : बांग्लादेश में जारी राजनीतिक उथल-पुथल और हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ने की सूचनाओं के बाद ऐसे लोगों की भी भारी संख्या बताई जा रही है जो भारत से लगी समुद्री सीमा को पार करने की जुगत में हैं। हाल में, ओडिशा के एक मंत्री ने आशंका जताई है कि भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और ओडिशा समुद्री पुलिस इस समुद्री इलाके में त्रिस्तरीय सुरक्षा बनाए हुए है, ताकि कोई अवैध घुसपैठ नहीं होने पाए। इसे शरण की कामना कहें या घुसपैठ ठहराएं-यहां सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश में सताए जा रहे हिंदुओं की खबर कौन लेगा। राजनीतिक रूप से हमारे नेतृत्व ने पहले तो अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को मदद मुहैया करवा कर अपनी नेकनीयती का परिचय दिया। साथ ही, बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते जुल्म के खिलाफ अपनी चिंता प्रकट की। लेकिन यहां सवाल उठाया जा सकता है कि बांग्लादेश के ऐसे पीड़ित हिंदू परिवारों को क्या इस समय भारत शरण नहीं दे सकता है, जिन्हें शायद बांग्लादेश में रह जाने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़े।

आप्रवासियों के आंकड़ों की विश्वसनीयता : वैसे तो भारत में बांग्लादेश से आए अवैध आप्रवासियों की सही संख्या का कोई विश्वसनीय आंकड़ा नहीं मिलता है। लेकिन वर्ष 1981, 1991, 2001 और 2011 की जनगणना में बांग्लादेश और भारत के लिए जनसंख्या वृद्धि और जनसांख्यिकी आंकड़ों के विश्लेषण से यह अनुमान मिलता है कि भारत में उनकी संख्या डेढ़ करोड़ से अधिक हो सकती है। इनमें से ज्यादातर लोग बांग्लादेश से सटे भारतीय इलाकों में बस गए हैं, जबकि कुछ लोग धीरे-धीरे और बेहतर जीवन स्तर और अच्छी नौकरी की तलाश में भारत के दूरदराज के इलाकों में भी पहुंचे हैं। यह सही है कि वैध दस्तावेजों के अभाव ने इनमें से अनेक लोग छोटी-मोटी नौकरियां ही कर रहे हैं, लेकिन ऐसे आरोप भी हैं कि इनमें से कुछ लोगों ने स्थानीय कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा की हैं। सीमावर्ती राज्यों में बांग्लादेशी नागरिकों की भारी मौजूदगी एक बड़े संकट की आहट मानी जाती रही है। इस बदलाव ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जनसांख्यिकी पैटर्न को बदल दिया है। इससे स्थानीय नागरिक बाहरी लोगों से स्वयं के लिए खतरा महसूस करते हैं। सीमावर्ती राज्यों के लोगों का यह दावा भी है कि बांग्लादेशियों की आबादी बढ़ने से स्थानीय लोगों का जीवन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। इससे दोनों पक्षों में तनाव और संघर्ष के हालात भी बने हैं। कुछ राज्यों में उग्रवाद पनपने और बढ़ने के पीछे भी बांग्लादेशी आप्रवासियों की भूमिका को देखा जाता है।

बांग्लादेश के हालिया हालात के मद्देनजर भारत जैसे सहिष्णु राष्ट्र के नेतृत्व और नागरिकों की यही आकांक्षा रहेगी कि वहां सताए जा रहे लोगों के बेहतर जीवन का कोई जरिया मिले और समस्या का समाधान निकले। लेकिन पहले ही भारी आबादी का बोझ उठा रहे और अपने नागरिकों के लिए रोजगार और संसाधनों का दबाव झेल रहे भारत में बांग्लादेश से अचानक आ रहे हजारों-लाखों लोगों को समाहित करना किसी भी दृष्टिकोण से समस्या का उचित समाधान नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि इसके लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों पर दबाव बनाया जाए और बांग्लादेश में ही इन सारे लोगों के लिए स्थितियां अनुकूल करने का प्रयास किया जाए। साथ ही, शरणार्थियों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय कानून पारित किए जाएं जिनमें शरण देने वाले देश के लिए अतिरिक्त संसाधनों का प्रबंध किया जाए। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया जाए कि यदि किसी विपदा में एक देश के नागरिकों को पड़ोसी मुल्क शरण देता है तो शरण की अवधि कितनी होगी और ऐसे लोगों के प्रवासन की वैधता का निर्धारण कैसे होगा। जब इन सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, बांग्लादेश से सटी सीमाओं पर चौकसी बरत कर घुसपैठ को रोकना एक उचित निर्णय कहा जाएगा।

राजनीतिक दांवपेच में फंसा आप्रवासन का मुद्दा

पूर्वोत्तर राज्यों में बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ का मुद्दा भारत के लिए एक बड़ा सिरदर्द रहा है। पिछली सदी के आठवें-नौवें दशक में असम में बांग्लादेश से आए अवैध आप्रवासियों की संख्या बहुत अधिक थी। उस दौर में ऐसे लोगों का मतदाता के रूप में नामांकन भी कर लिया गया था। इसके विरोध में असम में 1979-1985 के बीच आंदोलन चला। इस असम आंदोलन में इन लोगों के तत्काल निर्वासन की मांग की गई थी। भारतीय संसद ने इस समस्या को हल करने के प्रयास में वर्ष 1983 में अवैध प्रवासी (ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारण) अधिनियम पारित किया, लेकिन यह उपाय कोई प्रभाव डालने में विफल रहा। इन अंततः 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को रद कर दिया। असम में चले आंदोलन की परिणति असम समझौते के रूप में हुई जिस पर 15 अगस्त, 1985 को केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा असम आंदोलन का नेतृत्व करने वाले आल असम स्टूडेंट्स यूनियन और आल असम गण संग्राम परिषद के नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे।

इस समझौते में यह परिकल्पना की गई थी कि 25 मार्च, 1971 को या उसके बाद असम में प्रवेश करने वाले सभी विदेशी नागरिकों की पहचान की जाएगी। इसके उपरांत उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे और बाद में विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत उन्हें निर्वासित किया जाएगा। लेकिन इस दिशा में बहुत कम प्रगति हुई। नागरिकता (संशोधन) विधेयक को इस कड़ी में महत्वपूर्ण पहल माना जाता है, जिसे 12 दिसंबर 2019 को कानून का जामा पहनाकर 10 जनवरी 2020 को लागू किया गया था। हालांकि यह कानून लागू करने के बाद असम, दिल्ली, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा तक में विरोध प्रदर्शन हुए जो बाद में पूरे देश में फैल गए। विधेयक में किए गए प्रविधानों के मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर हो रहे उत्पीड़न का सामना करने और उससे बचकर भारत आने वाले अल्पसंख्यकों को अवैध आप्रवासी नहीं माना जाएगा और उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसमें हालांकि उन छह पंथों के लोग शामिल थे जो अपने मूल देशों में अल्पसंख्यक थे। विधेयक के अनुसार 31 जनवरी 2014 से पहले ऐसे जितने भी प्रवासी भारत आए थे, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी।

(डा. संजय वर्मा)

खरी-खरी

चक्रव्यूह में राजनीति

नृपेंद्र अभिषेक नृप

जब बात राजनीति की होती है तो महाभारत का स्मरण आ ही जाता है। संसद में विपक्ष के नेता के द्वारा चक्रव्यूह की बात करते ही राजनीति में आजकल फिर से महाभारत चर्चा में आ गया है। वर्तमान भारत की राजनीति भी महाभारत के कुरुक्षेत्र से कम नहीं है। यहां हर नेता स्वयं को अर्जुन समझता है, लेकिन जब चुनावी मैदान में उतरता है, तो कर्ण बनकर 'विस्फोटक' बयान देने से पीछे नहीं हटता। अपने बयान से महाभारत करवा देने वाले इस देश में चुनाव जीतने के लिए तो किसी भी हद तक जाते ही हैं, साथ ही संसद में भी कामेडी शो शुरू कर देते हैं।

आज के दौर में मोदी जी को यदि कृष्ण माना जाए, तो वे अपने चमत्कारी भाषणों और रणनीतियों से विपक्ष को धृतराष्ट्र जैसा अंधा साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसे में कांग्रेस के शीर्ष नेता की तुलना अभिमन्यु से करना कोई गलत नहीं होगा। वे हर बार चुनावी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, लेकिन निकलने का रास्ता अब तक नहीं खोज पाए हैं।

यादव समुदाय के सबसे बड़े 'भीम' अखिलेश हैं, जो सपा के गदाधारी नेता हैं। उनके पास भीम जैसी ताकत है, लेकिन कभी-कभी दुर्योधन के सामने वो कमजोर पड़ जाते हैं। शहर को द्रोणाचार्य कहा जा सकता है, जो सबकी चुनावी दांव-पेच सिखाने में माहिर हैं। उनके पास 'चाणक्य' की बुद्धिमत्ता और 'द्रोणाचार्य' की विद्या है, जिससे वे भाजपा को हर चुनावी जंग में विजय दिलाने का सामर्थ्य रखते हैं।

आज के 'महाभारत' में हर नेता स्वयं को धर्मराज युधिष्ठिर मानता है, लेकिन सच कहें तो राजनीति में सच्चाई और धर्मराज का कहीं अता-पता नहीं है। यहां हर कोई अपने-अपने 'स्वार्थ' के लिए कुरुक्षेत्र में उतरा है। जनता भी अब द्रोणाचार्य की तरह 'हस्तिनापुर' यानी दिल्ली की जीतने वालों के पीछे चलने को मजबूर है।

वर्तमान राजनीति में सत्य और धर्म केवल चुनावी घोषणाओं तक सीमित हो गए हैं, और जनता की भूमिका तो बस 'कुरुक्षेत्र' के रणभूमि में खड़ी 'विराट सेना' की तरह हो गई है, जिसे कोई भी पार्टी अपने पक्ष में 'अर्जुन' बनाने की कोशिश में लगी है।

पोस्ट

कोलकाता दुष्कर्म मामले की जड़ें काफी गहरी नजर आ रही हैं। यह बड़े पैमाने पर मानव अंग तस्करी का मामला लग रहा है, जिसके उजागर होने के डर से डाक्टर के साथ हतनी दरिंदगी की गई। कुछ सूत्र अस्पताल में चल रहे सेक्स और ड्रग रैकेट की ओर भी इशारा कर रहे हैं। बंगाल के एक बड़े नेता और उनके भतीजे पर भी शक की सुई। मंजीत ठाकुर@manjit2007

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को कोई दर्जा भी करेगा या यह सिर्फ एक्स या छिटपुट वेबसाइट्स पर ही सिमटकर रह जाएगा? किसी ने किताब लिखकर इसे स्थायी तौर पर डाक्यूमेंट करने की कोशिश की है? कोई फेलोशिप? कोई ग्रांट? सन्नाटा है। यहीं पर लेफ्ट और इस्लामवादी वाली बाजी मार ले जाते हैं। सुशांत झा@jhasushant

लज्जा मैंने भले ही 32 साल पूर्व लिखी हो, लेकिन बांग्लादेश में आज भी वही हो रहा है। हिंदुओं का उत्पीड़न जारी है। वे बांग्लादेश से पलायन को विवश हैं। बांग्लादेश की स्थिति अफगानिस्तान से भी बुरी होने जा रही है। जिहादियों की पकड़ मजबूत हो रही है। अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर यूनुस मौन है। तसलीमा नसरीन@taslimanasreen

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या रेल दुर्घटनाएं किसी आपराधिक साजिश का परिणाम हैं?

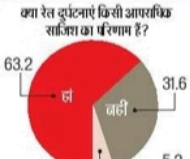

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

आप आइएमएफ की उप-प्रबंध-निदेशक गीता गोपीनाथ से सहमत हैं कि 2027 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक्री बन जाएगा?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

रक्षा बंधन पर को राखी की वह डोर,
पुन: ने पैदा हो सके कहीं निर्भया और।
कहीं निर्भय और बने हम ऐसे भाई,
हर दानव की तोड़ सके वैहियक कलाई।
मानवता की आज हो रही नीलाम पेक्षा,
ले नया रूप राक्षस करे नारी की रक्षा।

उत्तर प्रदेश डायरी

अजय जायसवाल
राज्य ब्यूरो प्रमुख, उत्तर प्रदेश

कोटे में कोटा और दलों के नफा-नुकसान

एससी-एसटी के आरक्षण में उप-वर्गीकरण (कोटे में कोटा) और क्रीमीलेयर तय कर उन्हें आरक्षण से बाहर करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय से उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों में भी वंचित समाज की राजनीति को लेकर नए सिरे से हलचल दिखाई दे रही है। यूं तो शीर्ष अदालत के निर्णय पर ज्यादातर दलों के पहले-पहल गोलमोल बयान ही आए, लेकिन राज्य में राजग के घटक दल निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद इस मसले पर भाजपा से अलग रुख अपनाते हुए कोर्ट के निर्णय का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। संजय सवाल करते हैं कि 'अनुसूचित जाति वर्ग के ही ज्यादा जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ देने के कोर्ट के निर्णय में गलत क्या है? एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमीलेयर होनी ही चाहिए। एससी/एसटी और ओबीसी में आरक्षण का लाभ पा चुके लोगों को आरक्षण छोड़ना चाहिए।' संजय को लगता है कि वोट बैंक घटने के डर से कई बड़े दल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध कर रहे हैं।

पहली अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तत्काल बाद भले ही विभिन्न दलों का रुख गोलमोल रहा हो, लेकिन अब सत्ताधारी भाजपा के साथ ही कांग्रेस, बसपा, सपा आदि पार्टियां एससी-एसटी आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था में किसी तरह की छेड़छाड़ के पक्ष में नहीं हैं, परंतु राज्य में निषाद पार्टी का रुख सबसे अलग है। पूर्वांचल में खासतौर से निषाद-मछुआ समाज की राजनीति करने वाले संजय निषाद को लगता है कि ज्यादा जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ देने संबंधी निर्णय के साथ खड़े होने से ही उनकी पार्टी को फायदा होगा, इसलिए वह भाजपा के सुर में सुर नहीं मिला रहे हैं। संजय के रुख पर भाजपा नेता चुप हैं, लेकिन माना जा रहा है कि संबंधित में छेड़छाड़ की आशंका से लोकसभा चुनाव में तगड़ा नुकसान झेल चुकी भाजपा को इस बात का अच्छे से अहसास है कि यदि उसने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का समर्थन किया तो विरोधी और ज्यादा ताकत से उस पर हमलावर होंगे। यही कारण है कि कोर्ट के निर्णय से पल्ला झाड़ते हुए भाजपा कह रही है कि आरक्षण पर आंबेडकर के बनाए संविधान में जो व्यवस्था है, वह उससे अलग नहीं जाएगी। ऐसा करके भाजपा ने कांग्रेस, सपा व बसपा से पहले वंचित समाज की राजनीति पर बढ़त लेने की कोशिश की है।

एससी-एसटी के आरक्षण को लेकर पीठासियक निर्णय से सुर्खियों में है उच्चतम न्यायालय। फाइल

विपक्षी दलों में खासतौर से वंचित समाज की राजनीति करनेवाली बसपा प्रमुख मायावती को लगता है कि कोर्ट के निर्णय की मुखालफत कर वह फिर वंचित समाज में अपनी मजबूत पैठ बना सकती है। यही कारण है कि मीडिया के माध्यम से मायावती कोर्ट के निर्णय पर असहमति जताते हुए इसे निष्प्रभावी करने के लिए संसद में विधेयक लाए जाने की वकालत कर रही हैं। कोर्ट के निर्णय पर राजग सरकार के साथ-साथ कांग्रेस, सपा की भी कठघरे में खड़ा कर मायावती आरोप लगा रही हैं कि सभी एससी-एसटी के आरक्षण के विरुद्ध हैं। वह कहती हैं कि यदि भाजपा की नीयत साफ है तो कोर्ट के फैसले को पलटकर, आरक्षण को संविधान की नौंवी अनुसूची में रखे। कोर्ट के निर्णय के 10 दिन बाद भाजपा-कांग्रेस के रुख को देखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि 'किसी भी प्रकार के आरक्षण का मूल उद्देश्य उपेक्षित समाज का सशक्तीकरण होना चाहिए, न कि उस समाज का विभाजन या विघटन, इससे आरक्षण के मूल सिद्धांत की ही अवहेलना होती है। अनगिनत पीढ़ियों से चले आ रहे भेदभाव और मौकों की गैर-बराबरी की खाई चंद पीढ़ियों में आए परिवर्तनों से पाटी नहीं जा सकती।' अखिलेश, भाजपा पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप भी लगाते हैं। अंततः कांग्रेस भी कोर्ट के निर्णय को संसद के जरिए निरस्त करने की बात कहते हुए भाजपा पर आरक्षण खत्म करने के प्रयास का आरोप लगा रही है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश में 2018 में गठित सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने की भी सुगबुगाहट दलों में दिख रही है। जस्टिस राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में गठित न्याय समिति ने ओबीसी में जातियों का वर्गीकरण करते हुए पिछड़ा वर्ग को सात प्रतिशत, अति पिछड़ा वर्ग को 11 प्रतिशत और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को नौ प्रतिशत आरक्षण देने की सिफारिश की थी। चूंकि समिति का गठन भाजपा सरकार ने ही किया था इसलिए माना जा रहा है कि सपा के पीडीए (पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक) फार्मूले की काट के लिए भाजपा, समिति की रिपोर्ट को देर-सबेर लागू कर वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव चल सकती है। अपने वोट बैंक को साधने के लिए भाजपा की सहयोगी सुभासपा जहां सर्वाधिक पिछड़ी जातियों को अलग कोटा देने, वहीं निषाद पार्टी उपवर्गीकरण की मांग तो कर ही रही हैं।

रक्षाबंधन

सामाजिक समरसता का पर्व

श्रावण मास का भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व है, क्योंकि इस मास से त्योहारों का आरंभ होता है। रक्षाबंधन पर्व का महत्व इस नाते भी कहीं अधिक हो जाता है

आचार्य राघवेंद्र प्रसाद तिवारी
कुलपति, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा

भारतीय पर्व सांस्कृतिक-सामाजिक एकता, सौहार्द, भाईचारे एवं पारस्परिक संबंधों की अनुपम सृजना हैं। उत्सवप्रिय भारतीय समाज पर्वों के माध्यम से आनंद प्राप्ति के साथ ही जीवन में सकारात्मकता का संचार, पूर्वजों के कृतित्वों की मधुर स्मृति, परंपरा का संवहन आदि करता है। श्रावण मास भारतीय संस्कृति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मास से पर्वों एवं उत्सवों की शुरुआत होती है। इसी कड़ी में श्रावण शुक्ल की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है।

भविष्य पुराण में वर्णित है कि देव और दानवों के बीच युद्ध में जब दानव भारी पड़ने लगे तब इंद्रदेव बृहस्पति आदि के साथ गए। बृहस्पति के कहने पर इंद्रदेव ने श्रावण पूर्णिमा की तिथि थी। तत्पश्चात इंद्रदेव ने इस पवित्र धागे की शक्ति से दानवों को पराजित किया। तभी से श्रावण पूर्णिमा के दिन इस पवित्र धागे को रक्षासूत्र के रूप में बांधने की परंपरा चल पड़ी। महाभारत काल में युद्ध के दौरान एक दिन श्रीकृष्ण की उंगली घायल हो गई थी एवं द्रौपदी ने अपने पल्लू का टुकड़ा काटकर श्रीकृष्ण की घायल उंगली पर बांध दिया था। इसी उपकार के बदले श्रीकृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी मदद की थी। प्राचीन भारत में जब शिष्यगण शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात गुरुकुल से विदा लेते थे तो आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन्हें रक्षासूत्र बांधते थे।

आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जनजागरण के निमित्त भी इस पर्व का अवलंब लिया गया। रवींद्रनाथ ठाकुर ने बंग-भंग का विरोध करते समय रक्षाबंधन त्यौहार को बंगालवासियों के पारस्परिक भाईचारे तथा एकता का प्रतीक बनाकर इस त्यौहार का राजनीतिक प्रयोग किया। वर्ष 1905 में कर्जन ने बंग-भंग करके बंदे मातरम् के आंदोलन से भड़की एक छोटी चिंगारी को शोलों में बदल दिया।

विविधता से भरे भारत में रक्षाबंधन का यह उत्सव विविध नामों और भिन्न-भिन्न तरीकों से मनाया जाता है। उत्तराखंड में इसे श्रावणी कहते हैं। इस दिन यजुर्वेदी द्विजों का उपकर्म का यज्ञोपवीत होता है। कश्मीर में अमरनाथ की विश्वविख्यात धार्मिक यात्रा गुरु पूर्णिमा से आरंभ होकर रक्षाबंधन के दिन पूर्णता को प्राप्त होती है। मान्यता है कि इसी दिन यहां का हिमानी शिवलिंग भी अपना पूर्ण आकार ग्रहण करता है। राजस्थान में रक्षाबंधन के दिन प्रकृति संरक्षण हेतु वृक्षों को भी राखी बांधने की परंपरा है। महाराष्ट्र का कोली समुदाय रक्षाबंधन को नारली पूर्णिमा या नारियल दिवस उत्सव के रूप में मनाता है। इस दिन वे समुद्र के देवता भगवान वरुण का आशीर्वाद लेने के लिए उन्हें नारियल चढ़ाते हैं।

भारतवर्ष में राखी बड़े हर्सोल्लास के साथ मनाई जाती है। बाजार रंग बिरंगी राखियों एवं मिठाइयों से भर जाते हैं। बाजार और व्यापार में उछाल आता है जिससे सबको आर्थिक लाभ मिलता है। सामाजिक समरसता की दृष्टि से भी इस पर्व का विशेष महत्व है। समाज के सभी वर्ग के स्त्री-पुरुष इस त्यौहार में भाग लेते हैं। किसी ने किसी को भी मन से अपना भाई या बहन मान लिया तो वे राखी के माध्यम से उस रिश्ते की डोर को मजबूत करते हैं और आजीवन उसे निभाते भी हैं। सुरक्षा के प्रतीक रक्षाबंधन के दिन प्रकृति संरक्षण हेतु वृक्षों को भी या लुंबा बांधने की परंपरा है। महाराष्ट्र का कोली समुदाय रक्षाबंधन को नरली पूर्णिमा या नारियल दिवस उत्सव के रूप में मनाता है। इस दिन वे समुद्र के देवता भगवान वरुण का आशीर्वाद लेने के लिए उन्हें नारियल चढ़ाते हैं।

रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के अटूट रिश्ते को दर्शाता है। प्रतीकात्मक

इस प्रकार रक्षाबंधन का पर्व भाई-बहन के साथ ही संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में पिरोने में महती भूमिका निभाता है। लेकिन देश की एकता एवं अखंडता को चुनौती भी मिलती रहती है। वर्तमान में देश में जाति एवं धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने के कुत्सित प्रयास निरंतर चल रहे हैं। बाहरी ताकतें भी देश को अस्थिर करने का षड्यंत्र करती रहती हैं। पड़ोसी देशों में स्थिति बिगड़ रही है। वहां पर चरमपंथी प्रभाव बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में भारत में भी विघ्नसंतोषी लोग सक्रिय हो जाते हैं। बुद्धिमत्ता इसी में है कि पड़ोस में यदि आग लगी हो तो अपना घर को सुरक्षित रखें। कोई दे मत नहीं है कि जब तक राष्ट्र सुरक्षित है, हम तभी तक सुरक्षित हैं। अतएव राष्ट्र की सुरक्षा ही समस्त नागरिकों का सर्वोपरि कर्तव्य होना चाहिए। ऐसे में सभी भारतवासी देश की एकता-अखंडता एवं सुरक्षा के दृढ़निश्चय के संकल्प द्वारा ही मानवता के दुश्मनों के मंसूबों को विफल कर सकते हैं। रक्षाबंधन के पवित्र अवसर पर हमारे राष्ट्र-धर्म-संस्कृति की सुरक्षा की भावना फलीभूत हो। रक्षाबंधन का यह त्योहार विविधता से भरे देश को एकत्व, सामंजस्य और सामरस्य के सूत्र में अनवरत पिरोता रहे, इसी विश्वास के साथ सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक

दैनिक जागरण
पर्व हमारी संस्कृति के प्रतिनिधि होते हैं

परिवारवादी दलों की कहानी

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने पार्टी छोड़ने की अटकलों के बीच अपनी जो शिकायती चिट्ठी जारी की, उससे स्पष्ट है कि वह झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ने का मन बना चुके हैं। चम्पाई सोरेन को हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया था। यह लगभग तय था कि हेमंत सोरेन जमानत पर बाहर आने के बाद फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल सकते हैं। अंततः ऐसा ही हुआ और हेमंत सोरेन ने विधानसभा चुनावों तक प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं समझा। चम्पाई सोरेन को जिस तरह मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, वह निःसंदेह अपमानजनक था। यह उनकी चिट्ठी से भी प्रकट हो रहा है, लेकिन उन्हें इसका आभास होना चाहिए था कि परिवारवादी दलों में परिवार के बाहर का कोई नेता कितना भी अनुभवी और वरिष्ठ क्यों न हो, शीर्ष पद पर उसका दावा कभी नहीं बनता। झारखंड मुक्ति मोर्चा अन्य अनेक क्षेत्रीय दलों की तरह से एक परिवारवादी दल है और ऐसे दलों में अन्य नेताओं की दाल एक सीमा तक ही गलती है। चम्पाई सोरेन जिन परिस्थितियों में झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने की कगार पर आ गए, उससे परिवारवादी दलों के तौर-तरीके ही उजागर हुए। जिस तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा में वही होगा जैसा सोरेन परिवार चाहेगा, वही स्थिति अकाली दल, राकांपा, उद्धव ठाकरे की शिवसेना समेत अन्य क्षेत्रीय दलों की भी है। इन दलों के वरिष्ठ नेता यह समझें तो बेहतर कि उनका राजनीतिक कद कभी भी परिवार के सदस्यों से बड़ा नहीं हो सकता।

चम्पाई सोरेन ने अपने सारे विकल्प खुले रखने की बात कही है, लेकिन माना जा रहा है कि वह भाजपा में शामिल होना पसंद करेंगे। पता नहीं ऐसा होता है या नहीं। वह अपना दल भी बना सकते हैं और भाजपा के सहयोगी दल में भी शामिल हो सकते हैं। जो भी हो, यदि वह भाजपा में आते हैं तो उनके लिए उससे तालमेल बैठाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि भाजपा अलग रीति-नीति वाली पार्टी है। हो सकता है कि भाजपा उन्हें अपने साथ लेने के लिए तैयार हो, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उनके आने से भाजपा के कुछ नेताओं के समक्ष मुश्किल खड़ी हो सकती है। भाजपा को यह नहीं भूलना चाहिए कि जब अन्य दलों के नेता उसके पाले में आते हैं तो उसके प्रतिबद्ध नेताओं और उनके समर्थकों को कहीं न कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ता है। चूंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव निकट हैं, इसलिए नेताओं के पाला बदलने के भरे-पूरे आसार हैं। भाजपा को इसके प्रति सतर्क रहना होगा कि बाहरी नेताओं का आगमन इस तरह से न हो कि उसके अपने नेताओं को अपना राजनीतिक भविष्य कठिनाई में पड़ता दिखाई दे। फिलहाल कहना कठिन है कि झारखंड के विधानसभा चुनावों में क्या स्थिति बनेगी, पर इतना अवश्य है कि हेमंत सोरेन को सत्ता विरोधी रुझान का सामना करना पड़ रहा है।

सुनिश्चित हो कार्यान्वयन

थानों को बेहतर बनाने की दिशा में बिहार सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयास तभी सार्थक हो पाएंगे, जब कार्यान्वयन के स्तर पर गंभीरता होगी। संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं तो रखरखाव भी आवश्यक है, ताकि उसकी उपयोगिता बनी रहे। लेकिन हाल के जांच में यह बात सामने आई है कि बिहार के 32 जिलों के 155 थानों में सीसी कैमरों का संचालन तक सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। यह बकई में बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि आज के समय में सीसी कैमरे की उपयोगिता लगभग हर जगह है। इसे पुलिस से बेहतर कौन समझ सकता है, क्योंकि विभिन्न मामलों के अनुसंधान में सीसीटीवी फुटेज का सहारा बहुत सामान्य बात है। इसके उपयोग से कई बार अपराधी आसानी से पकड़े भी गए हैं। अब यदि थानों में ही इसकी उपेक्षा हो तो औरों से क्या अपेक्षा की जा सकती है। ऐसे में बिहार राज्य की पुलिस को तकनीकी संसाधन से लैस करने की जो पहल की गई है, उसे गति देना जरूरी है। पहले संसाधन का रोना था। सरकार जब संसाधन दे रही है तो उसका रखरखाव तक सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। इससे कार्यशैली भी पता चलती है कि थानों का संचालन किस तरह किया जा रहा है। किसी भी संस्थान में सबसे पहले वहां की व्यवस्था ही आम जन के मन में सकारात्मक या नकारात्मक भाव पैदा करती है। यही कारण है कि इसमें सुधार के लिए कई पहल भी की गई हैं। जब संसाधन का रखरखाव ही नहीं होगा तो उसके उपयोग की बात ही बेमानी है।

> आम नागरिक यह समझता है कि पुलिस है तो वह सुरक्षित है। इसके लिए यह आवश्यक है कि नागरिक सुरक्षा के लिए जो भी व्यवस्था बनाई जा रही हो, उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित हो

व्यापक लाभ वाला पूंजीगत खर्च

विवेक देवराय

आदित्य सिन्हा

सरकार बुनियादी ढांचा निर्माण पर जो राशि खर्च करती है, उससे वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही भविष्य के लिए भी अवसर सृजित होते हैं

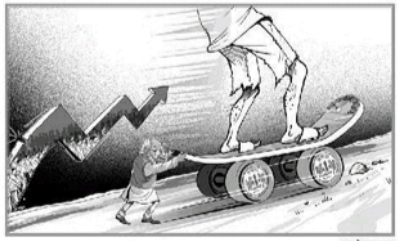
अवधेश राजपूत

कोविड महामारी के बाद और इस समय जारी भू-राजनीतिक उथलपुथल के दौर में जहां दुनिया के तमाम हिस्से पुरानी आर्थिक तेजी हासिल करने के लिए संघर्षरत हैं, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत स्पष्ट दिखते हैं। देश में उपभोग का स्तर भी बढ़ा है। इसके बावजूद कुछ आर्थिक दबाव अब भी कायम हैं, जैसे कि निर्यात का मोर्चा, जो व्यापक रूप से बाहरी वैश्विक परिदृश्य पर निर्भर करता है। ऐसे में वृद्धि की गति देने के लिए सरकारी व्यय की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। सरकारी व्यय को भी मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक होता है चालू व्यय, जिसमें वेतन और सब्सिडी जैसे सामान्य एवं परिचालन लागतों से जुड़े खर्च शामिल होते हैं। दूसरा होता है पूंजीगत व्यय जिसे कैपेक्स भी कहते हैं। इसमें बुनियादी ढांचे का निर्माण जैसी ऐसी परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, जो लंबे समय तक उपयोग में लाई जाती हैं। इसमें वित्तीय हस्तांतरण के माध्यम से कल्याणकारी कार्यक्रमों के रूप में धन का पुनर्वितरण होता है। वस्तुओं और सेवाओं की लागत को नियंत्रण में रखने के लिए सब्सिडी दी जाती है और सार्वजनिक निवेश बढ़ाया जाता है। इसके अंतर्गत शोध, विकास एवं लोक उपक्रमों पर खर्च किया जाता है। अपनी उत्पादक प्रकृति के चलते पूंजीगत व्यय जीडीपी वृद्धि पर व्यापक प्रभाव डालता है। यह न केवल सड़क, स्कूल और कारखानों के निर्माण जैसी परियोजनाओं के माध्यम से तात्कालिक मांग को प्रोत्साहन देता है, बल्कि आर्थिकी की उत्पादन क्षमताओं में वृद्धि के जरिये दीर्घकालिक आर्थिक विस्तार की आधारशिला रखता है।

प्रश्न उठता है कि पूंजीगत व्यय अन्य खर्चों से कैसे बेहतर है? इसे मल्टीप्लायर इफेक्ट यानी गुणक प्रभाव की अवधारणा से समझा जा सकता है। इस प्रकार के खर्च में सरकार द्वारा आर्थिक स्तर पर जो राशि खर्च की जाती है वह अर्थव्यवस्था पर चक्रीय प्रभाव दिखाकर उसके एक बड़े हिस्से को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। जैसे सरकार किसी हाईवे के निर्माण पर जो खर्च करती है, उससे कंस्ट्रक्शन में आपूर्तिकर्ताओं से लेकर कामगारों के लिए अवसर बनते हैं। उन्हें आय अर्जित होती है। इस आय से कुछ लोग वस्तु और सेवाओं का उपभोग करेंगे तो कारोबारी अपने व्यवसाय में पुनः निवेश करेंगे। इस पैसे से जो कारोबार सृजित होगा, उससे अन्य लोगों के लिए भी रोजगार सृजित होंगे। यह प्रक्रिया चलती रहती है और हर एक चरण के साथ सरकार के आरंभिक निवेश में चक्रीय प्रभाव उत्पन्न होता रहता है। वस्तुतः गुणक प्रभाव से यही आशय है कि इसमें सरकारी खर्च केवल परियोजना में प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय लोगों तक ही सीमित नहीं रहता, अपितु यह आर्थिकी के विभिन्न स्तंभों पर असर डालते हुए समग्र आर्थिक वृद्धि को संबल प्रदान करता है।

संभव है कि सभी प्रकार के सरकारी व्यय इस प्रकार का प्रभाव न उत्पन्न न कर पाएं। सुरन्या बोस और एनआर भानुमूर्ति के एक शोध के अनुसार पूंजीगत परियोजनाओं (बुनियादी ढांचे जैसी) पर खर्च अन्य प्रकार के खर्चों की तुलना में कहीं व्यापक प्रभाव डालता है। ऐसी परियोजनाओं पर सरकार जो एक रुपया खर्च करती है वह 2.45 रुपये के खर्च जितना प्रभाव उत्पन्न करता है। इसके उलट, सरकार नकदी हस्तांतरण (कल्याण और पेंशन) और सामान्य व्यय (जैसे कि वेतन) पर जो एक रुपया खर्च करती है, उसका प्रभाव 0.98 से 0.99 रुपये के बराबर पड़ता है। यानी अपने मूल के जितना भी नहीं। इससे स्पष्ट है कि पूंजीगत परियोजनाओं पर खर्च न केवल तात्कालिक तौर पर अर्थव्यवस्था की गति बढ़ाता है, बल्कि बुनियादी ढांचे में सुधार, उत्पादकता में बढ़ोतरी और भावी आर्थिक गतिविधियों को आधार प्रदान कर दीर्घकालिक वृद्धि की ठोस बुनियाद भी रखता है। सीधे शब्दों में कहें तो सरकार सड़क, स्कूल या अस्पताल जैसी परियोजनाओं पर जो खर्च करती है, उससे न केवल वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, बल्कि भविष्य के लिए भी अवसरों का सृजन होता है। यह निवेश लोगों के जीवन को सुविधाजनक बनाता है। कारोबार को सुगम बनाता है। रोजगार बढ़ाता है। इससे दीर्घकाल में एक सशक्त अर्थव्यवस्था की राह तैयार होती है।

वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में सरकार ने पूंजीगत व्यय के लिए 11.1 लाख करोड़ रुपये का प्रविधान किया है। यह जीडीपी के 3.4 प्रतिशत के बराबर आवंटन है। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 17.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। यह बढ़ोतरी बुनियादी ढांचा विकास एवं दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है। हाल के वर्षों में सरकारी निवेश के दम पर ही बुनियादी ढांचे के विकास ने गति पकड़ी है। वर्ष 2019 से 2023 के बीच इस मोर्चे पर हुआ 49 प्रतिशत निवेश सरकार द्वारा किया गया। पिछले एक दशक के दौरान देश में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है। इनमें अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बंदरगाह और हाईवे से लेकर ब्राडबैंड कनेक्टिविटी जैसे प्रमुख काम गिनाए जा सकते हैं।

सुनिश्चित किया जा रहा है कि दुर्गम इलाकों में भी स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाएं पहुंचें। आयुष्मान भारत योजना के जरिये किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दूरदराज के क्षेत्रों में भी आधुनिक अस्पताल और आरोग्य मंदिर स्थापित किए जा रहे हैं। तमाम मेडिकल कालेज और अस्पताल निर्माण की प्रक्रिया में हैं। करीब 60,000 तालाबों का पुनरुद्धार किया गया है तो दो लाख पंचायतों को आप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा गया है। नहरों का फैलता जाल भी किसानों को लाभ पहुंचा रहा है। इसके साथ ही चार करोड़ पक्के मकानों का निर्माण हाशिए पर रहने वाले लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने में सेतु की भूमिका निभा रहा है। इसी कड़ी में तीन करोड़ और मकानों के निर्माण की भी बात है। सरकार का यह दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उसी संकल्पना के अनुरूप है, जिसका उल्लेख उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में 'ईज़ आफ लिविंग' यानी जीवन की सुगमता के रूप में किया।

(देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में ओएसडी-अनुसंधान हैं)

response@jagran.com

खतरा बनते बांग्लादेशी घुसपैठिये

हरेंद्र प्रताप

संताल परगना में मुस्लिम आबादी में अप्रत्याशित वृद्धि मुख्य रूप से बांग्लादेशी घुसपैठियों से हुई है

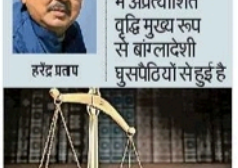
घुसपैठियों से मुक्ति दिलाए न्यायिक तंत्र। प्रतीकात्मक

पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्तापलट की घटना के बाद वहां अराजकता फैली हुई है। ऐसे में वहां से एक बार फिर बड़े पैमाने पर घुसपैठियों के भारत आने की आशंका पैदा हो गई है। इससे झारखंड, असम और बंगाल जैसे राज्य प्रभावित हो सकते हैं। वैसे बांग्लादेश से मुस्लिमों की घुसपैठ की समस्या दशकों पुरानी है। आजादी के बाद वर्ष 2011 तक राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू 4.28 प्रतिशत घटे, लेकिन झारखंड के संताल परगना में हिंदू 22.42 प्रतिशत घटे। कुल जनसंख्या में जनजाति/आदिवासी समाज भी 44.66 से घटकर 28.11 प्रतिशत पर आ गया। यानी इसकी आबादी में 16.55 प्रतिशत की कमी आई। राष्ट्रीय स्तर पर ईसाई जनसंख्या वृद्धि दर 231 प्रतिशत थी तो संताल परगना में यह 674% प्रतिशत से ज्यादा थी। राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम भले ही 4.31 प्रतिशत बढ़े हों, पर संताल परगना में 13.3 प्रतिशत बढ़े। इस कारण वहां जनजाति समाज का पलायन हो रहा है।

वर्ष 1951 में संताल परगना की कुल जनसंख्या 23,22,092 थी, जिसमें हिंदू 20,98,492 (90.37 प्रतिशत), मुस्लिम 2,19,240 (9.43 प्रतिशत) तथा ईसाई 4,289 (0.18 प्रतिशत) थे। कुल जनसंख्या में जनजातीय लोग 10,37,167 (44.66 प्रतिशत) थे। 2011 की जनगणना में संताल परगना की कुल जनसंख्या 69,69,097 हो गई, जिसमें हिंदू 47,35,723 (67.95 प्रतिशत), मुस्लिम 15,84,285 (22.73 प्रतिशत), ईसाई 2,93,718 (4.21 प्रतिशत) थे। कुल जनसंख्या में जनजातीय लोग 19,59,133 (28.11 प्रतिशत) थे। संताल परगना अब पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, देवघर, दुमका और जामताड़ा यानी छह जिलों में बंट गया है। आंकड़े बताते हैं कि 1961 से 2011 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम आबादी 3.54 प्रतिशत बढ़ी, पर इनकी आबादी साहिबगंज में 14.7 प्रतिशत, पाकुड़ में 13.84 प्रतिशत, जामताड़ा में 8.91 प्रतिशत, गोड्डा में 7.39 प्रतिशत तथा देवघर में 5.82 प्रतिशत बढ़ी। इसी दौरान जनजाति/आदिवासी समाज की जनसंख्या पाकुड़ में 14.53 प्रतिशत तथा साहिबगंज में 12.66 प्रतिशत घटी।

संताल परगना की आबादी में हो रहे इस अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव को देखते हुए गत वर्ष झारखंड हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। इसमें यह आरोप लगाया गया कि झारखंड के कुछ जिलों में सुनियोजित तरीके से मुस्लिमों की घुसपैठ कराई जा रही है तथा आदिवासी लड़कियों से विवाह कर उनका मतांतरण कराया जा रहा है।

वहां स्थित मदरसों में देश विरोधी कार्य हो रहे हैं। ऐसे 46 मदरसों की सूची भी न्यायालय को सौंपी गई। इस पर कोर्ट ने केंद्र एवं राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। राज्य सरकार की विशेष शाखा ने भी प्रदेश के सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों को एक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया कि संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवेश की सूचना मिली है। ये घुसपैठिये विभिन्न मदरसों में आकर ठहरते हैं, सरकारी दस्तावेज तैयार कर अपना नाम मतदाता सूची में चढ़वाते हैं और वहीं बस जाते हैं। इनके अन्य जिलों में भी प्रवेश की आशंका है। इसके बावजूद राज्य सरकार के अधिकारियों ने कोर्ट में दिए शपथपत्र में घुसपैठ को अस्वीकार कर दिया। इस पर नाराज कोर्ट ने आइबी, बीएसएफ और चुनाव आयोग को प्रतिवादी बनाया है तथा सभी को शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।

संताल परगना बहुत पहले से इसलामिक ताकतों की नजर में रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना में 5,857 मुस्लिम जनजाति दर्ज हैं। इन दिनों जनजाति लड़कियों से मुसलमान लोभ-लालच देकर विवाह कर रहे हैं, ताकि वे जनजाति समाज की भूमि पर कब्जा कर सकें। उनकी जमीनों को कब्जा करने के लिए लव जिहाद चलाया जा रहा है। संताल परगना में मुस्लिम राजनीति भी काफी प्रभावी है। जिस इलाके में मुस्लिम प्रभावी हो जाते हैं उसे काटकर अलग प्रखंड बनवा लेते हैं। जैसे कि देवघर जिले के कैरी प्रखंड में 1961 में मुस्लिम आबादी मात्र 23 प्रतिशत थी। इससे काटकर मार्गो मुंडा प्रखंड बनाया गया है, जहां अब मुस्लिम आबादी 48.35 प्रतिशत हो गई है। गोड्डा जिले के पथरगामा प्रखंड में 1961 में मुस्लिम आबादी 19.18 प्रतिशत थी। इससे काटकर बसंतराई प्रखंड बना है जहां अब मुस्लिम आबादी 50.02 प्रतिशत है। साहिबगंज जिले के राजमहल से काटकर बने उधवा प्रखंड में भी मुस्लिम आबादी अब 63.73 प्रतिशत है। इन बांग्लादेशी घुसपैठियों ने संताल परगना में आतंक मचा रखा है। साहिबगंज की रेबिका पहाड़िन और दुमका की अंकिता सिंह की निर्मम हत्या की कहीं राष्ट्रीय मीडिया में चर्चा नहीं हुई। दिलदार अंसारी ने रेबिका के 50 टुकड़े कर दिए थे। वहीं अंकिता सिंह को नर्सिंग ने पेट्रोल डाल कर जला दिया था।

झारखंड में 2016 में बनी डोमिसाइल नीति इस समस्या को और बढ़ा रही है, जो बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों एवं घुसपैठियों में अंतर नहीं करती। भूमिहीन के मामले में ग्रामसभा को पहचान का जो अधिकार दिया गया है, उसका लाभ लेकर मुस्लिम मुखिया एवं सरपंच के माध्यम से घुसपैठिये स्थानीय होने का बागज बनवा लेते हैं। विगत पांच दशक में असम में मुस्लिम जनसंख्या 8.92 प्रतिशत बढ़ने पर न्यायालय ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनाने का आदेश दिया था। जबकि झारखंड के साहिबगंज और पाकुड़ जिले में तो 14 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम आबादी बढ़ी है। मुस्लिम आबादी में हुई यह भारी वृद्धि भारतीय मुसलमानों के कारण नहीं, बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण है। झारखंड हाई कोर्ट ने इन घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से निकालने के लिए जो पहल की है वह स्वागतयोग्य है। आशा है कोर्ट एनआरसी की भी पहल करेगा।

(लेखक बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

रक्षाबंधन

सदियों से श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता रहा है। साहित्य में इससे जुड़े अनेक पौराणिक-ऐतिहासिक आख्यानों की भरमार है। कालांतर में राजा-महाराजा इस दिन विशेष रूप से रक्षा सूत्र का प्रयोग करते थे। वैसे कभी भी इसका उपयोग हो सकता है। द्वापरयुग में कृष्ण की बहन सुभद्रा ने रक्षाबंधन की परंपरा को आरंभ किया। इससे पहले त्रेतायुग में मुनियों, संत-महात्माओं और ब्राह्मणों ने राम को रक्षासूत्र भेंट कर रक्षा का सांकेतिक विश्वास प्रकट किया था। सतयुग में धर्म और सत्य की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र का महत्व रहा, क्योंकि देवताओं और राक्षसों के युद्ध में अनेक बार रक्षासूत्र के प्रयोग अपनाए गए।

समय के साथ इस पर्व की परंपरा में नए-नए आयाम जुड़ते गए। यह भाई-बहन के रिश्ते के भाव एवं दायित्वों को भी रेखांकित करता है। इस दौरान बहन द्वारा भाई को रक्षासूत्र समर्पित करके सुरक्षा का अधिकार अर्जित करना इसका प्रचलित उद्देश्य है। रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति और समाज का सर्वाधिक संवेदनशील पर्व है। अन्य पर्व प्रायः धर्म संप्रदाय से आबद्ध हैं, परंतु रक्षाबंधन सांस्कृतिक दर्शन का स्रोत है। इसे सभी लोगों में एक-दूसरे के प्रति रक्षा के विश्वास का ही महापर्व कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। वैसे यह एकता का पर्व सर्वव्याप्त है।

रक्षाबंधन असंभव को संभव बना सकता है। एक शत्रु भी रक्षासूत्र में बंधकर मित्र बन जाता है। यह पर्व सद्भावना एवं मित्रता का संदेश देता आया है। कभी यह देवताओं और राक्षसों के मध्य शांति का ध्वज बन गया था। अनेक समस्याएं, चाहे वे कितनी ही कठिन से कठिन हों, रक्षासूत्र के अधीन सामान्य समस्या में बदल जाती हैं। अर्थात रक्षाबंधन से विकट समस्याएं हल हो जाती हैं। राखी का आध्यात्मिक महत्व भी है। यह मात्र धागे का बंधन नहीं है, बल्कि सशक्त अनुभूति की गांठ है। भावनाओं की अमर गाथा है।

डा. राघवेंद्र शुक्ल

हवाई क्षेत्र में हरित क्रांति

ठौंद्रराज सुथार

> दिल्ली एयरपोर्ट शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल करने वाला भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया है

दिल्ली एयरपोर्ट भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जिसने शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया है। शुरुआत में इसने 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अक्षय ऊर्जा के उपयोग, ग्रीन एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने सहित विविध उपायों से लक्ष्य को समय से पहले ही हासिल कर लिया है।

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई अभिनव और प्रभावी उपाय किए हैं। एयरपोर्ट पर कुल ऊर्जा खपत का लगभग छह प्रतिशत हिस्सा एयरसाइड और कार्गो टर्मिनलों की छतों पर स्थापित सौर पैनलों से बनाया है। यह भारत में किसी भी हवाई अड्डे द्वारा अक्षय ऊर्जा का सबसे बड़ा उपयोग है। हवाई अड्डे ने अपने बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग शुरू किया है, जिसने पेट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहनों की जगह ली है। इसके अलावा वाहनों पर विशेष डिवाइस लगए गए हैं, जो ईंधन की खपत को कम करने में मदद करते हैं। अगर चालक वाहन को तय से अधिक गति से चलाता है या परमिट एरिया से अलग कहीं लेकर जाता है, तो नियंत्रण कक्ष को जानकारी मिल जाती है। इन उपायों से न केवल कार्बन उत्सर्जन में कमी आई, बल्कि ईंधन की खपत में करीब चौथाई बचत हो रही है। हरित हवाई अड्डे के लिए बुनियादी ढांचे का विकास भी महत्वपूर्ण रहा है। इसका उदाहरण है देश का पहला एलिवेटेड टैक्सी वे, जो विमानों को एक रनवे से दूसरे रनवे या रनवे से टर्मिनल तक जाने में कम दूरी तय करने में मदद करता है। इस नवाचार से एक साल में 8,82,200 किलो कार्बन उत्सर्जन कम हो रहा है।

यह उपलब्धि दर्शाती है कि बड़े पैमाने पर संचालन वाली संस्थाएं भी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार हो सकती हैं। महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन न केवल संभव है, बल्कि लाभदायक भी हो सकता है। यह भारत के अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं जैसे पेरिस समझौते के तहत किए गए वादों के अनुरूप है। वैसे शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करना एक सतत प्रक्रिया है। लिहाजा दिल्ली हवाई अड्डे को अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। यह उपलब्धि अन्य हवाई अड्डों और बड़े बुनियादी ढांचे के लिए एक माडल के रूप में काम कर सकती है। हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश न केवल पर्यावरण के लिए लाभदायक है, बल्कि यह नए रोजगार के अवसर पैदा करता है और अर्थव्यवस्था को नई दिशा देता है। पर्यावरण संरक्षण एक सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रत्येक नागरिक भी अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण के प्रति जागरूक रहकर योगदान दे सकता है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

सरकारों को जगाने के लिए हड़ताल जरूरी

'हड़ताल नहीं है समाधान' संपादकीय पढ़ा। डाक्टर कभी भी बेवजह हड़ताल नहीं करते हैं और न ही सड़क और रेल रोक आमजन को परेशान करते हैं। यह तो सही है कि किसी भी समस्या का समाधान हड़ताल नहीं है, इससे आमजन ही प्रभावित होता है, लेकिन हमारे देश में सरकारें किसी भी मुद्दे पर तब तक नहीं जागतीं जब तक उन्हें जगाने के लिए हड़ताल, धरने-प्रदर्शन न हों और मीडिया इसके लिए गंभीरता न दिखाए। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज में एक ट्रेनी महिला डाक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई, उसे भी रफा-दफा कर दिया जाता अगर इसके लिए सारे देश के डाक्टर एकजुट होकर हड़ताल न करते और मीडिया इसे सुर्खियों में न रखता। कितनी शर्मनाक और निंदनीय है कि जिस देश में लड़कियों की रक्षा के लिए रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, वहां आज भी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। असली सवाल तो यह है कि देश में दुष्कर्म की घटनाएं क्यों नहीं रुक रहीं? इनमें शामिल हैवान क्यों फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचते? क्यों कानून दरिंदों को सख्त सजा देने में देरी करता है? आखिर देश में बेटियां कब सुरक्षित होंगी? देश में दुष्कर्म के बढ़ते अपराध बहुत बड़ी चिंता का विषय हैं। अगर इन पर नकेल कसने के लिए अभी गंभीरता नहीं दिखाई गई या फिर महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रयास सरकार और समाज ने मिल-जुलकर नहीं किए तो आने वाला समय महिलाओं के लिए इससे भी विकट हो सकता है। सख्त कानून के साथ जब तक लोगों में नैतिकता की भावना का प्रचार-प्रसार नहीं होगा तब तक ऐसी घिनौनी घटनाओं पर रोक लगना मुश्किल है।

raju09023693142@gmail.com

मेलबाक्स

ममता बनर्जी का प्रपंच

ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं यानी संपूर्ण प्रदेश की सर्वेसर्वा, जिनके हाथ में पुलिस, प्रशासन और स्वास्थ्य सेवाएं भी हैं। लेकिन कोलकाता के एक अस्पताल में घटित वहशियाना घटना को लेकर स्वयं ममता द्वारा सड़क पर महिला मार्च और धरना प्रदर्शन करके आखिरकार किसके विरुद्ध आवाज उठाई जा रही है? रात के अंधेरे में सैकड़ों लोगों का तथाकथित उग्र प्रदर्शन, अस्पताल व छात्रों के धरनास्थल पर तोड़फोड़ का मतलब क्या है? बंगाल का पुलिस प्रशासन कितना डरा-सहमा व असहाय लगता है। उपद्रवियों द्वारा की गई अराजकता का सारा ठीकरा ममता ने 'वाम' और 'राम' पर फोड़ दिया, जो पल्ला झाड़ राजनीति की एक नायाब मिसाल नहीं है तो क्या है? निस्संदेह 'राम' शब्द बंगाल की सरकार के विरुद्ध राजनीतिक दुस्वारियां पैदा कर सका है, क्योंकि अब देश के साधु-संत भी राजनीति में भगवान राम के नाम को लेकर ममता सरकार से अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि हत्या शरीर को नष्ट करती है, जबकि दुष्कर्म आत्मा को अपवित्र और अपमानित करता है। डाक्टर से दुष्कर्म व हत्या से पूरे देश में उबाल है। स्वयं एक महिला होने के नाते ममता को चाहिए था कि इस मामले को गंभीरता से लेतीं।

दीपक गौतम, सीनौपत

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव

जम्मू-कश्मीर में तीन चरणों 18 व 25 सितंबर और एक अक्टूबर को विधानसभा चुनावों की घोषणा स्वागत योग्य है। पिछले कुछ महीनों से जम्मू क्षेत्र में सीमा पार से आतंकी घुसपैठ और सेना पर हमलों से यह स्पष्ट होने लगा था कि पाकिस्तान के भी जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और डिलिमिटेशन की प्रक्रिया के पश्चात केंद्र सरकार की चुनाव संपन्न कराने की योजना सकार रूप ले चुकी थी। जम्मू-कश्मीर की जनता ने भी इस बदलाव को स्वीकार कर लिया। नए राजनीतिक वातावरण में चुनाव में भाग लेने वाले दलों के सामने अपने घोषणापत्र में राज्य के विकास, युवाओं को रोजगार, स्वास्थ्य, उद्यम, कृषि, पर्यटन को पंख लगाने और आतंकवाद को समूल नष्ट करने की प्राथमिकता है।

बिनोद जौहरी, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 157

एक कदम पीछे

खनन पर कर लगाने का राज्यों का अधिकार 1 अप्रैल, 2005 की तारीख से प्रभावी तथा बरकरार रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने एक ओर जहां राजकोषीय संघवाद के सिद्धांतों को मजबूती प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर उसने खनन कंपनियों पर भारी वित्तीय देनदारी भी थोपी है।

उद्योग जगत के मुताबिक निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के खनन करने वालों को इस फैसले के पुरानी तारीख से लागू होने के कारण 1-2 लाख करोड़ रुपये की चपत लग सकती है। केंद्र सरकार ने न्यायालय से कहा कि अकेले सरकारी क्षेत्र की खनन कंपनियों पर इस फैसले से करीब 70,000 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा। न्यायालय द्वारा तय अंतिम तिथि सशर्त है, मसलन कोई ब्याज या जुर्माना नहीं लगेगा और भुगतान 12 वर्षों में किया जाएगा। इससे कुछ राहत मिली है।

सर्वोच्च न्यायालय ने अतीत की तिथि से लागू करने के बारे में स्पष्टीकरण दिया है कि निर्णय को भविष्य में लागू करना उचित नहीं होगा। उसका यह तर्क दिखाता है कि उच्चतम स्तर पर भी न्यायपालिका में काम की गति कितनी धीमी है। सन 1989 में सात न्यायाधीशों के पीठ ने इंडिया सीमेंट और तमिलनाडु राज्य एवं अन्य के मामले में कहा था कि खनिज उत्खनन की रॉयल्टी टैक्स नहीं है। उसने कहा कि केवल सीमेंट पर कर लगाया जा सकता है जबकि राज्य सरकार केवल रॉयल्टी वसूल सकती है। पांच न्यायाधीशों के पीठ ने 2004 में टाइपिंग की एक गलती की ओर इशारा करते हुए इस निर्णय को उलट दिया। उसने कहा कि रॉयल्टी कर नहीं है लेकिन रॉयल्टी पर लगने वाला उपकर (जो तमिलनाडु सरकार ने लगाया था लेकिन इंडिया सीमेंट उसका विरोध कर रही थी) कर है और ऐसे अतिरिक्त उपकर वसूल करना राज्यों का अधिकार है। इसके परिणामस्वरूप कई राज्यों ने अपने-अपने यहां खनिज खनन पर ऐसे कर लगाने के अधिकार का इस्तेमाल किया। इस बीच न्यायिक चुनौतियां भी उत्पन्न हुईं। आखिर में सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी चुनौतियों के परीक्षण के लिए एक पीठ का गठन किया। उसने कहा कि उसके निर्णय के भावी इस्तेमाल से ऐसी स्थिति बनेगी जहां राज्यों द्वारा खनन पर लगने वाले कर के लिए बने कानून अवैध होंगे और उन पर यह दबाव बनेगा कि वे सक्षम कानून के माध्यम से कर के रूप में संग्रहित राशि को वापस करें। वित्तीय बोझ के अलावा अतीत से प्रभावी करों का देश में एक विवादास्पद इतिहास रहा है और अतीत में उसने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी नुकसान पहुंचाया है। वर्ष 2007 में एस्सार टेलीकॉम द्वारा हचिंसन से वोडफोन का अधिग्रहण किए जाने के बाद वित्त अधिनियम 2012 द्वारा पूंजीगत लाभ पर अतीत से कर लगाने के मामले में 2022 में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने निरस्त कर दिया था। वर्ष 2012 के कानून के नुकसानदेह असर के चलते सरकार ने 2021 में उस कानून को ही निरस्त कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निस्संदेह खनिज समृद्ध राज्यों की वित्तीय स्थिति को बदलेगा। दो अगस्त को झारखंड ऐसा विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया जिसने अपनी सीमा के भीतर होने वाले खनिज-कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट और मैंगनीज पर उपकर लगाया। ओडिशा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ इससे लाभान्वित होने वाले अन्य राज्य हैं। परंतु इस निर्णय के मुद्रास्फीतिक प्रभाव के पहलू को देखते हुए अकेले कोयले पर लगने वाला कर कीमतों में इजाफे की वजह बन सकता है। राज्यों के लिए अच्छा होगा कि वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन्हें दिए गए विवेकाधिकार का इस्तेमाल करें। इससे निर्णय का प्रभाव कम हो सकेगा और उन्हें लाभ होगा।

पड़ोसी का सम्मान होगी सही रणनीति

अगर हमें अपने पड़ोसियों के प्रति नए ढंग से सम्मान प्रदर्शित करना है तो पीड़ित बनने, घरेलू राजनीति और अत्यधिक धार्मिकता से निजात पाने की आवश्यकता है।

बांग्लादेश के घटनाक्रम ने एक बार फिर भारत के पड़ोस को सुर्खियों में ला दिया है। साथ ही ऐसी स्थितियों से निपटने के मोदी सरकार के रिकॉर्ड पर भी सबकी नजर है। आज के हालात पर गहराई से नजर डालने के लिए हमें चौथाई सदी पहले जाना होगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर की बस यात्रा कर पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की बड़ी पहल की थी। उन्होंने कहा था कि हम अपने मित्र चुन सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। वर्ष 2008 में मनमोहन सिंह ने एक कदम आगे बढ़ाया और 'पड़ोसी प्रथम' का नारा दिया। 2014 में नरेंद्र मोदी ने भी इस पर मुहर लगाई और अपने शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय उपमहाद्वीप के सभी देशों के नेताओं को आमंत्रित किया। इसके बाद उन्होंने पड़ोसी मुल्कों की यात्रा की। एक बार तो उनकी यात्रा बेहद नाटकीय रही, जब वह बिना किसी को बताए पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पोती की शादी में मुबारकबाद देने लाहौर पहुंच गए।

उस समय उम्मीद जगी थी। 25 साल में पहली बार बहुमत की सरकार चला रहे देश का मुखिया अगर ऐसे सात संप्रभु देशों के बीच रिश्तों में सुधार के लिए इतना प्रतिबद्ध है, जिनके बीच कई मतभेद थे तो मतभेदों और टकरावों को दूर कर सभी के बीच सेतु बनाना मुमकिन था। हालांकि इन देशों के बीच कुछ मतभेद विचारधारा के कारण थे, जो समय के साथ गहरे हो गए थे। शीतयुद्ध के दौर के पूर्वग्रह भी इनके बीच थे। इन समस्याओं से निजात पाकर राह बनाना बड़ी चुनौती थी, जिसके लिए मोदी आगे बढ़ रहे थे।

अब मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल चल रहा है तो देखना होगा कि उनका प्रदर्शन कैसा रहा है? बांग्लादेश अब तक के सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। बीते 15 सालों से बांग्लादेश भारत का सबसे करीबी सहयोगी रहा है। भारत के लिए सुरक्षित पूर्वोत्तर की धुरी ढाका में है क्योंकि म्यांमार में शक्ति का केंद्र कहां है, कोई नहीं जानता। इस बीच पाकिस्तान में नाटकीय बदलाव आए हैं। वहां नया सत्ता प्रतिष्ठान है और 5 अगस्त, 2019 को जम्मू कश्मीर में हुए बदलावों के बाद भारत के साथ उसके संबंध लगभग समाप्त हो चुके हैं।

राष्ट्र की बात
शेखर गुप्ता

नेपाल में अविश्वास इतना बढ़ चुका है कि उसने अपने राष्ट्रीय मानचित्र में बदलाव करके सामरिक महत्त्व के उस भारतीय भूभाग को अपना हिस्सा दिखा दिया, जहां से कैलास-मानसरोवर तीर्थ यात्रा का मार्ग गुजरता है। नेपाल की संसद में इस मानचित्र को सर्वसम्मति से मंजूरी भी मिल गई।

श्रीलंका में आर्थिक संकट के बाद एक अलग किस्म की क्रांति हुई। हंबनटोटा जैसे उसके प्रमुख बंदरगाह का चीन ने अधिग्रहण कर लिया। मालदीव में मोहम्मद मुइज्जू के उभार के पीछे 'भारत भगाओ' का नारा रहा और यह हाल ही की बात है। भूटान पर सीमा विवाद 'हल' करने का चीनी दबाव लगातार बना हुआ है और उससे कहा जा रहा है कि इसमें 'भारत के हितों की परवाह नहीं की जाए'।

क्या यह नाटकीय और बदतर दौर पूरी तरह भारत की गलतियों का नतीजा है? या भारत पीड़ित है? मगर इतने रसूख वाला भारत पीड़ित होने का दावा कैसे कर सकता है? आज हमारा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) शेष उपमहाद्वीप के कुल जीडीपी का चार गुना है। हमारी आबादी उनकी तीन गुना और वैश्विक शक्ति कई गुना है। भारत की जनता ने अपने गणतंत्र को पड़ोसी मुल्कों की तुलना में विशिष्ट बनाया है: एक संवैधानिक लोकतंत्र बनाया है, जहां सब कुछ लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और विश्वसनीय तरीके से होता है। इसलिए पीड़ित होने की बात छोड़ ही दीजिए।

दुनिया में सबसे अस्थिर पड़ोस हमारा ही है। ज्यादातर पड़ोसियों की आबादी बहुत अधिक है और शहरों में भीड़भाड़ है। उनकी आबादी में युवा ज्यादा हैं और अफ्रीकी देशों के उलट ज्यादातर ने लोकतंत्र को अपनाया है। बड़ी युवा आबादी और लोकतंत्र का अर्थ है कि जनता की राय मायने रखती है।

शेख हसीना और उनके मित्र के रूप में भारत ने बांग्लादेश में इसी बात की अनदेखी की। ये ऐसे देश नहीं हैं जहां कोई बेहद ताकतवर तानाशाह जनता की राय के खिलाफ जा सकता है। उनमें से हर एक देश का लोकतंत्र हमारी तुलना में अपूर्ण है लेकिन उनमें से किसी में पूरी तरह तानाशाही भी नहीं है। इन सभी देशों में आपको शासन और जनता के विचारों दोनों का ध्यान रखना होता है।

जनमत के लिए संप्रभुता भी मायने रखती है। अगर भारत दबाव बनाता नजर आएगा तो अच्छी प्रतिक्रिया नहीं होगी। हम नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश में ऐसा होते देख चुके हैं। 2015 की नाकेबंदी ने गहरा जख्म दिया है। विदेश मंत्रालय यह जानता है और अक्सर सही बात कहता है। परंतु हमारा मीडिया खासकर सरकार के मित्रवत कहलाने वाले हिंदी समाचार चैनलों पर आने वाली खबरों पर गहरी नजर रखी जाती है। चरम राष्ट्रवादी सोशल मीडिया हैंडल उन्हें बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते हैं। कुछ हैंडल तो बांग्लादेश में सेना भेजने, वहां रहने वाले 1.4 करोड़ हिंदुओं के लिए सीमाएं खोल देने और रंगपुर में उनके लिए बस्ती बनाने की सलाह तक दे रहे हैं।

मालदीव के साथ बिगड़ रहे संबंध सुधारने के लिए वहां गए विदेश मंत्री एस जयशंकर जिस दिन लौटे उसी दिन अफवाह फैल गई कि मालदीव ने 28 द्वीप भारत को सौंप दिए। कुछ हिंदी चैनलों के प्राइम टाइम में इस पर बहस तक हो गई। किसी ने कह डाला कि 'मुइज्जू ने घुटने टेक दिए।' हमारे लिए यह मजाक हो सकता है, मालदीव के लोगों के लिए नहीं। करीब 50 लाख की आबादी और सात अरब डॉलर जीडीपी वाला वह देश भी हमारी तरह संप्रभु है। आखिर में विदेश मंत्रालय ने सभी ट्वीट डिलीट कराए मगर तब तक देर हो चुकी थी। खुद को उस पड़ोसी की जगह रखकर देखिए। वे यही सुनते समझते होंगे कि भारत बहुत दबंगई से काम करता है। दबंगई अच्छी है लेकिन मानसिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और बौद्धिक गुणों का क्या? स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में कहा था विनम्रता के साथ क्षेत्र में शिक्षक बनना होगा। क्या हमारे शिक्षा संस्थान इतने अच्छे हैं कि वे पड़ोसी देशों के उन हजारों विद्यार्थियों को लुभा सकें, जो शिक्षा के लिए विदेशों में जाते हैं? क्या हम चाहते हैं कि वे आएं? चरम राष्ट्रवादी मीडिया द्वारा अपमान की जगह छात्रवृत्ति, इंटर्नशिप, सांस्कृतिक प्रदर्शन और फिल्में हों तो कैसा हो? इकलौती महाशक्तियों का इतिहास बताता है कि सॉफ्ट पावर असल में हार्ड पावर या असली ताकत की सहायक नहीं है बल्कि उसके लिए बहुत जरूरी है। क्या भारत में ऐसे थिंक टैंक हैं जो पड़ोसी देशों के विद्वानों को जगह दें, उन्हें सम्मेलनों के लिए बुलाएं, खुद की ट्रैक-2 प्रक्रिया चलाएं? ऐसा नहीं है कि भारत को यह सब पता नहीं है। इसीलिए हम नेपाल और भूटान से तो बिजली खरीदते हैं लेकिन बांग्लादेश को बिजली निर्यात करते हैं।

दूसरा पहलू है हिंदू कार्ड का जरूरत से अधिक प्रयोग। प्रधानमंत्री की नेपाल और बांग्लादेश यात्राओं के दौरान मंदिर भ्रमण को खास तौर पर प्रचारित किया गया। मगर हकीकत यह है कि हमारी सबसे लंबी सीमाएं मुस्लिम बहुल देशों के साथ मिलती हैं। जब हम उनसे कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ अच्छा व्यवहार करें तो वे हमारी ओर सवालिया ढंग से देखते हैं। यह गजब ही है कि बांग्लादेश उबल रहा है और हमारी कूटनीति हालात संभालने में लगी है ठीक उसी समय एक बांग्लादेशी हिंदू को असम में सीएए के तहत नागरिकता प्रदान की गई।

पांच वर्ष से और खासकर यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद से भारत बहुध्रुवीयता, सामरिक स्वायत्तता और बहु-संबद्धता की बात करता रहा है। मगर हमारे पड़ोसी भी इस पर चल सकते हैं। अगर हम चीन के खिलाफ अमेरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं तो उन सभी के पास हमारे विरुद्ध चीन है। ताकतवर अमेरिका भी अपने पड़ोसी देश क्यूबा को नहीं झुका सका। वेनेजुएला को भी नहीं। पड़ोसियों के साथ हमारी नीति वही होनी चाहिए जो वाजपेयी ने बनाई, मनमोहन सिंह ने अपनाई और जिसे मोदी ने ऊर्जा प्रदान की। हमें बस घरेलू राजनीति और अंध धार्मिकता से बचना होगा। साथ ही पड़ोसियों के प्रति अधिक नरमी दिखानी होगी और सम्मान बरतना होगा।

भारत की रक्षा खरीद और शक्ति संतुलन

सेना को हथियारबंद बनाना आसान काम कभी नहीं रहा। 1960 के दशक के आरंभ में भारतीय वायु सेना के सामने कठिन प्रश्न था कि उसे कौन सा लड़ाकू विमान चुनना चाहिए? भारतीय नौसेना के पास पहले ही ब्रिटिश युद्ध पोत थे, इसलिए वायु सेना ने सोवियत संघ से लाइसेंस लेकर मिग-21 बनाने का निर्णय लिया। हथियार खरीदार के रूप में हमारे आरंभिक दिनों में ही अंतरराष्ट्रीय हथियार बाजार की सबसे बुनियादी हकीकत खुलकर हमारे सामने आई - हथियार खरीद का चयन केवल तकनीक या लागत पर आधारित नहीं होता बल्कि इसे चुनते समय विदेश नीति और रणनीति का बहुत ध्यान रखा जाता है। हाल ही में मध्यम दूरी के विविध भूमिका वाले लड़ाकू विमान के चयन में भी देश के सामने यही दुविधा आई। युद्ध में प्रभाव, कीमत और लाने-ले जाने की सुविधा के हिसाब से भारत शायद फ्रांस के राफेल की जगह स्वीडन के ग्रिपेन फाइटर का चयन करता। किंतु फ्रांस के राजनयिक और कूटनीतिक वजन, परमाणु शक्ति के उसके दर्जे तथा अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में उसकी तकनीकी बढ़त को देखते हुए दसाँ का राफेल विमान होड़ में जीत गया।

ऐसी ही वजहों से नौसेना अपने तथाकथित प्रोजेक्ट-75, इंडिया के तहत छह एयर इंडिपेंडेंट प्रॉपल्शन (एआईपी) पनडुब्बियों की खरीद पर विचार ही कर रही है और एक दशक बाद भी किसी निर्णय पर पहुंचने में कामयाब नहीं हो सकती है। देश में पनडुब्बियों से जुड़े किसी भी व्यक्ति से बात कीजिए और वह जर्मन पोत निर्माता एचडीडब्ल्यू का नाम लेगा, जिसकी टाइप 209 पनडुब्बियां 1980 के दशक के मध्य से ही सेवा दे रही हैं। जनवरी 2005 में जर्मनी के पोत निर्माता समूह टिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स (टीकेएमएस) ने एचडीडब्ल्यू का अधिग्रहण कर लिया था। टिसेनक्रुप मरीन सिस्टम्स भारत के महागांव डॉक (एमडीएल) के साथ अहम साझेदारी में टाइप 214 एआईपी पनडुब्बियां बनाने जा रही है। परंतु स्वीडन की ही तरह जर्मनी भी हथियारों की बिक्री में राजनयिक या कूटनीतिक तौर पर अहम नहीं है, इसलिए प्रोजेक्ट 75-आई अनाथ की तरह पड़ा है।

हथियारों की बिक्री, तकनीकी नियंत्रण, सामरिक गठजोड़ और औद्योगिक साझेदारी के बीच का संबंध पश्चिमी लोकतांत्रिक गठबंधन ऑकस के उदय में भी सामने आया है। ऑकस (ऑस्ट्रेलिया-यूनाइटेड किंगडम-अमेरिका) करीबी सहयोगी देशों के बीच बनी व्यवस्था है। क्वाड के दो सहयोगियों भारत और जापान को इसमें जगह नहीं दी गई है। ऑकस की बुनियाद ऑस्ट्रेलिया को 12 परमाणु चालित हथियारबंद पनडुब्बियों के लिए तकनीकी साझेदारी मुहैया कराने के लिए भी रखी गई है। इससे लगभग तय माना जा रहा एक सौदा खत्म हो गया है और वह है फ्रांसीसी पोत निर्माता नेवल ग्रुप से पारंपरिक ऊर्जा से चलने वाली 12 हथियारबंद शॉर्ट फिन बाराकुडा पनडुब्बियों की खरीद।

दोधारी तलवार
अजय शुक्ला

ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी तकनीक मुहैया कराने के चौंकाने वाले फैसले का स्पष्ट रणनीतिक उद्देश्य था ताइवान के आसपास चीनी हमले की स्थिति में ऑस्ट्रेलिया का समर्थन हासिल करना। अनुमान था कि ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन चीन के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ देंगे। हालांकि ऑस्ट्रेलिया का समर्थन तभी तय हो गया जब 2018 में स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने। उस समय अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह साथ लेने के लिए यह साहसी कदम उठाया। अमेरिका चाहता था कि अमेरिकी नौसेना जरूरत पड़ने पर ऑस्ट्रेलियाई अड्डों और उसकी नौसैनिक सुविधाओं का पहले से अधिक लाभ उठाएं। यह पहले ही कहा जा चुका है कि 2024 के समापन से पहले ऑकस के तीनों देश एक त्रिपक्षीय अलगोरिद्म बनाएंगे ताकि पी-8 सोनोबॉय से चीनी पनडुब्बियों के बारे में जानकारी जुटा सकें। यह ऑकस की पहली ठोस पिलर 2 तकनीक होगी, जिससे काम लिया जाएगा। क्षमता में ये मामूली वृद्धि वैसी ही सम्मिलित और दूरदर्शी हैं, जैसी ऑकस समझौते में चाही गई हैं। इस बीच भारत शक्ति संतुलन का विकल्प चुनने के लिए जूझ रहा है। एक ओर उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो तथा पश्चिमी लोकतंत्रों के समर्थन वाला यूक्रेन है तो दूसरी ओर चीन तथा कुछ अन्य देशों (जो उतने लोकतंत्र समर्थक नहीं हैं) से समर्थन पाने वाला रूस है। रूस के समर्थन में वे देश हैं, जिन्हें संघर्ष के इस घटनाक्रम में गुपचुप हथियार खरीद का अवसर दिख रहा है। भारत लड़ाकू विमानों, मध्यम भार ढोने वाले हेलीकॉप्टरों, बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, एयर डिफेंस गन, फ्रिगेट, पनडुब्बी आदि के लिए रूसी और सोवियत दौर के हथियारों पर निर्भर है। लेकिन उसे रूस के अलावा दूसरे देशों से मिलने वाले उपकरणों की भी बड़ी सूची है, जिसमें भारी और हल्के परिवहन विमान तथा हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी, एरोस्पेस इंजन और समुद्री गैस टरबाइन आदि शामिल हैं। भारत को विकल्प चुनते समय ध्यान रखना होगा कि रूस समर्थन देने से चीन के सैन्य और रक्षा उद्योग को भी फायदा होगा।

रूस हो या चीन, हथियार खरीद के लिए विदेश पर निर्भरता ही अच्छी बात नहीं है। यही कारण है कि रक्षा मंत्रालय आत्मनिर्भरता पर इतना अधिक जोर दे रहा है। उसकी प्रमुख स्वदेशीकरण संबंधी पहल 'इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस - डिफेंस इनोवेशन ऑर्गनाइजेशन (आईडेक्स-डीआईओ)' को रक्षा अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला बताया जा रहा है।

रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत डीआईओ द्वारा स्थापित आईडेक्स सफलतापूर्वक आगे बढ़ा है और रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप को अच्छी गति प्रदान की है। इस समय वह 400 स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मझोले उपक्रमों के साथ काम कर रहा है। अब तक 2,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 37 सामग्री की मंजूरी दी जा चुकी है।

सैन्य विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ का काम है जिसने शोध के लिए नौ क्षेत्र चिह्नित किए हैं। ये हैं प्लेटफॉर्म, हथियार प्रणाली, सामरिक प्रणालियां, सेंसर और संचार प्रणालियां। अंतरिक्ष, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और रोबॉटिक्स, मटीरियल और डिवाइस तथा सैनिक सहायता भी इनमें शामिल हैं।

इन पहलों की बदौलत कई आधुनिक उत्पाद सामने आए जिनमें 155 मिमी आर्टिलरी गन धनुष, तेजस लड़ाकू विमान, जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल प्रणाली, अर्जुन टैंक, ध्रुव हल्के हेलीकॉप्टर आदि शामिल हैं। एक मानवरहित विमान का पूर्ण और सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकी विकास कोष भी उद्योगों को 10 करोड़ रुपये की राशि प्रदान करता है।

रक्षा मंत्रालय ने रक्षा हथियारों और उपकरणों की चार सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां (पीआईएल) जारी की हैं, जिनमें से किसी भी उपकरण या हथियार के आयात की इजाजत नहीं है। 101 उत्पादों वाली पहली पीआईएल अगस्त 2020 में जारी की गई थी। 108 उत्पादों की दूसरी सूची मई 2021 में और 101 उत्पादों की तीसरी सूची अप्रैल 2022 में जारी की गई थी। नवीनतम पीआईएल गत माह जारी की गई।

इतना ही नहीं 26,000 से अधिक रक्षा उत्पादों को रक्षा मंत्रालय के सृजन पोर्टल पर अपलोड किया गया है और निजी क्षेत्र को उन्हें देश में ही बनाने के लिए कहा गया है। इनमें से 7,032 उत्पादों का स्वदेशीकरण हो चुका है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 2018-19 के बाद से रक्षा आयात 46 फीसदी से घटकर 36.7 फीसदी रह गया है। परंतु आत्मनिर्भरता की तलाश अभी जारी है।

आपका पक्ष

सड़कों पर गड्ढों, जलजमाव की समस्या दूर हो

बारिश के कारण कई क्षेत्रों में सड़कों पर जलजमाव होने लगता जिससे सड़कें पानी से लबालब भर कर तालाब बन जाती है। ऐसा नजारा देश की कई जगहों में बारिश के बाद अक्सर देखने को मिल जाता है। पानी भरी सड़क पर लोग चल नहीं पाते हैं। पानी के कारण बाइक बंद होकर फंस जाती है और चार पहिया वाहन की दुर्गति हो जाती है। हर साल बारिश के दिनों में सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे उभर आते हैं जिससे दुर्घटना की संभावना काफी बढ़ जाती है। सड़कों पर उभरे गड्ढों को समतल कर, सड़कों के किनारे नालियों से गाद निकाल कर यातायात को सुचारु रूप से चलाया जा सकता है। बारिश का पानी घरों, दुकानों आदि में घुसकर सामान को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ जनजीवन को भी प्रभावित करता है। तेज बारिश के कारण कई गांव, शहर प्रभावित होते हैं तथा वहां की कई संरचनाओं को भी नुकसान पहुंचता है। बाढ़ आने पर आपदा प्रबंधन लोगों को बचाने का कार्य करता है लेकिन घरों, मकानों तथा अन्य संरचनाओं की मरम्मत का कार्य लोगों को अपनी जेब से ही करना पड़ता है। भारी बारिश के बाद नदियों में जलस्तर बढ़ने पर सरकार पुल-पुलिया पर उफनती नदी को पार नहीं करने की हिदायत अथवा चेतावनी देती है। मगर जलजमाव होने से सड़कों पर पड़े गड्ढों में पानी भर जाने पर वहां कोई चेतावनी का बोर्ड नहीं दिखता जिससे गड्ढे में गिरने की वजह से वाहन चालक, राहगीर घायल हो जाते हैं। सड़कों के गड्ढे भरने के साथ ही नालियों की सफाई आवश्यक है। ताकि बारिश जनित समस्याओं से निजात मिल सके।

संजय वर्मा, धार

कोलकाता में रविवार को भारी बारिश के बाद पानी से भरी सड़क से गुजरते वाहन तथा राहगीर

सरकारी स्कूलों की सुधरे दशा

सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने के लिए सख्त कदम उठाना अनिवार्य हो गया है। वर्तमान में स्कूलों की बदहाली किसी से छुपी नहीं है। इस वजह से अभिभावकों को निजी स्कूलों का रुख करना पड़ता है जहां फीस इतनी है कि गरीब व्यक्ति के बस की बात नहीं रह जाती है। निजी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होती है। वहीं सरकारी स्कूलों में हिंदी माध्यम से पढ़ाई होती है। इससे सरकारी स्कूल के छात्र अंग्रेजी विषय में निजी स्कूलों के मुकाबले कमतर साबित होते हैं। सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के स्तर में उन्नयन के लिए आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। वर्तमान में सभी स्कूलों में आधुनिक तरीके से शिक्षा देने की जरूरत है जो तभी संभव है जब सरकारी स्कूलों में भी निजी स्कूलों की तरह आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराया जाए। नवोदय तथा केंद्रीय विद्यालय की तरह अन्य सभी सरकारी स्कूलों को सुविधाएं दी जाए। केवल नाम में उत्कृष्ट, मॉडल, सीएम राइज या पीएम श्री लगाने से स्कूलों की कायाकल्प नहीं हो सकती है। वर्तमान में शिक्षकों के अनेक पद रिक्त पड़े हैं। इन खाली पदों पर अतिथि शिक्षकों/ विशेषज्ञों से काम लिया जा रहा है। इसके लिए सरकार को सभी पात्र अतिथि शिक्षकों को नियमित करना चाहिए। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे की कमी को दूर किया जाना चाहिए।

मोहित सोनी, कुक्षी

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कुवैत के शहजादे शेख सबा अल-खालिद अल-सबा (दाएं) से मुलाकात की। इसके साथ ही जयशंकर ने वहां के प्रधानमंत्री शेख मुहम्मद सबा अल-सलेम अल-सबा से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए चर्चा की।

विचार
नवभारत टाइम्स
नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। सोमवार, 19 अगस्त 2024

पारदर्शिता बनी रहे

केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) की ओर से जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डेप्युटी सेक्रेटरी के 45 पदों पर लैटरल एंट्री की खातिर दिए गए विज्ञापन में कोई नई बात नहीं है। केंद्र सरकार की प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा में लैटरल एंट्री की पॉलिसी नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली NDA सरकार के पहले ही कार्यकाल में लाई जा चुकी है। इसके तहत कई दौर की नियुक्तियां भी हो चुकी हैं। फिर भी, इस बार राजनीतिक दल इसका ज्यादा तीखा विरोध कर रहे हैं।

विरोधी दलों की प्रतिक्रिया | कांग्रेस, RJD, समाजवादी पार्टी और BSP जैसे दलों ने इसके खिलाफ कड़े बयान जारी किए। सबसे बड़ी आपत्ति इस बात को लेकर है कि इन नियुक्तियों में SC/ST और OBC समूहों के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इन दलों का आरोप है कि जानबूझकर आरक्षण व्यवस्था को दरकिनार करने के लिए ही मौजूदा सरकार लैटरल एंट्री प्रक्रिया पर जोर दे रही है।

लैटरल एंट्री के विज्ञापन पर बवाल

तीखे विरोध के पीछे | इस तरह के तीखे विरोध की एक वजह तो यह हो सकती है कि इस बार नियुक्तियों की संख्या पिछले दौरों के मुकाबले काफी ज्यादा है। लैटरल एंट्री पॉलिसी के तहत पहले राउंड की नियुक्ति 2019 में हुई थी, जिसमें सिर्फ 9 पद भरे गए थे। 2021 और 2023 में हुई नियुक्तियों को जोड़ दिया जाए तो अब तक इस प्रक्रिया के तहत कुल 63 नियुक्तियां ही हुई हैं। दूसरी बात यह कि हालिया लोकसभा चुनावों में जो कुछेक मुद्दे अहम माने गए, उनमें कास्ट सेंसस और संविधान बदलने का डर भी शामिल है। संभवतः इसलिए भी विरोधी दल लैटरल एंट्री के इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं।

संदेह का माहौल न बने | वैसे सिद्धांत रूप में लैटरल एंट्री की पॉलिसी गलत नहीं कही जाएगी। ब्यूरोक्रेसी में फ्रेश टैलंट लाना, अलग-अलग क्षेत्रों में अनुभव और कुशलता हासिल कर चुके लोगों को इससे जोड़ना खासा उपयोगी हो सकता है। लेकिन यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि इसे लेकर समाज, राजनीति और प्रशासन के हलकों में संदेह का माहौल न बने।

जरूरी है खुलापन रखना | लैटरल एंट्री का प्रयोग आगे बढ़े, सभी पक्ष इसे पॉजिटिव ढंग से लें इसके लिए इस नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े कई पहलुओं पर और काम करने की जरूरत है। डोमेन एक्सपर्ट्स का इन सेवाओं से जुड़ना अच्छी बात है, लेकिन इस क्रम में अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस डर को खत्म करना भी जरूरी है कि लैटरल एंट्री रिजर्वेशन पॉलिसी को दरकिनार करने का जरिया बनेगी।

चक्र-व्यू

मीर होते तो..

राहुल पाण्डेय

हिंदुस्तान में अगस्त पैदाइशों का महीना है। आबादी की अगर ठीक से पड़ताल की जाए, एक-एक महीने की पैदाइशों को अलग किया जाए तो मेरा दावा है कि इस महीने से ज्यादा पैदाइशें शायद ही किसी और महीने के हवाले हों। मेरी जान में और नहीं तो एक दर्जन से ऊपर की पैदाइशें अगस्ती हैं। पिछले हफ्ते के आखिर में आई ऐसी ही एक पैदाइशी तारीख पर मुझे बुलाया गया। सब इकट्ठा हुए। सारे पके-पुराने लोग थे। बच्चों के मानिंद सबने रंग-बिरंगी टोपियां पहनी थीं। टोपियां गवाह थीं कि उनकी गवाहियां झूठी होती हैं। इसी बीच कच्ची कविताओं से पके हुए एक साहब ने मुझसे कहा कि बाकी चाहे जिस पर बात करें, आज आप सिर्फ कवियों पर बात करेंगे। मेरे लाख कहने के बावजूद कि भई, मेरा ताल्लुक न तो किसी कविता से रहा है, और न ही किसी कवि से कभी कोई ऐसा राब्ता रहा जो काबिल-ए-जिक्र हो। मैं कैसे कवियों पर बात कर सकता हूं? उन्हें नहीं मानना था, सो नहीं माने। कहने लगे, आप तो मीर पर लिखते हैं। फिर आपका ताल्लुक कविता से कैसे नहीं रहा? अब उनको ये कौन समझाए कि मीर कवि नहीं थे। मीर तो एक लठैत थे। लाठी भांजा करते थे। फिर कोई शायर की कवि कहके देख ले। आज का भी शायर कवि कहे जाने पर लाठी उठाने को तैयार रहता है।

Bhital Verma

साहब कहने लगे कि कवि की कविता पर कुछ न कहना हो तो लाठी पर ही बोल दीजिए। आजकल की कविता और लाठी में फर्क ही क्या बचा है? मैंने कहा, कविता और लाठी में बस एक फर्क बचा है, और वो है प्रकाशक का। प्रकाशक बढ़ा है तो लाठी कविता बन जाती है, और प्रकाशक ऐसे ही है तो कविता लाठी बन जाती है। प्रकाशक बढ़ा है तो कवि लाठी लेकर चलता है। प्रकाशक छोटा है तो कविता लाठी टिकाकर चलती है। कविता के नाम पर लाठी-लकड़ सब बिक रहा है। भावनाओं पर इतनी बड़ी चोट होने के बावजूद कोई अदालत का दरवाजा ही नहीं खटखटा रहा है। साहब के साथ-साथ कई और कविता पीड़ित पूछने लगे कि हालात मुसलसल इसी तरह क्यों रहते हैं भाई? मैंने कहा, कविता की जुबान जब लाठी की जुबान बन जाए तो हालात ऐसे ही हो जाते हैं। और लाठी कोई आज से ही ऐसे नहीं है। मीर ने अगर लठैती सीखी तो सबको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि क्यों सीखी थी। आज के कवि अगर कविता की जगह कुछ और लिख रहे हैं तो वजह बस इतनी ही है कि आज मीर नहीं हैं। मीर होते तो दो मिनट में कविता और लाठी का फर्क बता देते। साहब बोले, मगर मीर तो अगस्त में नहीं पैदा हुए थे। मैंने कहा, बस यही तो एक दिक्कत है। इसीलिए मीर भी क्रांति नहीं कर पाए।

एकदा

रक्षासूत्र से मिला उत्साह

यह प्रसंग उस समय का है जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। दोनों ओर ही युद्ध की विभीषिका को लेकर चिंता और तनाव व्याप्त था। युधिष्ठिर ज्येष्ठ भ्राता होने के कारण बेहद परेशान थे और इधर से उधर घूम रहे थे। तभी अचानक कृष्ण ने वहां पर प्रवेश किया। कृष्ण ने युधिष्ठिर के चेहरे पर उभरी चिंता की रेखाओं को भांप लिया। वह अपने चिर-परिचित अंदाज में मुस्कुराते हुए बोले, 'किस सोच में डूबे हो?' युधिष्ठिर बोले, 'ऐसा अनुमान है कि महाभारत का युद्ध एक महायुद्ध होगा। मैं अपने सैनिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं। इनकी सुरक्षा का कोई उपाय सुझाइए।' कृष्ण बोले, 'तुम्हारा युद्ध धर्म बचाने को लेकर है। युद्ध में तो हानि होती ही है। लेकिन हां, युद्ध में अन्याय की जीत कभी नहीं होनी चाहिए। इसलिए यह प्रयत्न करो कि सदाचार, सत्य और न्याय पृथ्वी पर बना रहे।' इस पर युधिष्ठिर बोले, 'हे विश्व ज्ञाता! जब आप सब कुछ जानते ही हैं तो फिर विजय का उपाय भी बताइए।' कृष्ण बोले, 'आज का दिन बेहद शुभ है। आज श्रावण मास की पूर्णिमा है। तुम आज के दिन अपनी पूरी सेना के हाथों में रक्षा का सूत्र बांध दो। यह रक्षा का सूत्र अवश्य ही अधर्म पर धर्म की जीत कराएगा।' कृष्ण की बातें सुनकर युधिष्ठिर के चेहरे से तनाव की रेखाएं मिट गईं। उन्होंने अपनी संपूर्ण सेना के हाथों में रक्षा का पवित्र सूत्र बांधा। इससे सेना का जोश सातवें आसमान पर जा पहुंचा। इतिहास गवाह है कि महाभारत के इस युद्ध में पांडवों की जीतहुई।

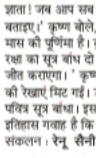
AI Image

संकलन : रेनू सैनी

सच्चे साथी की पहचान मुश्किल वक्त में, पड़ोसी देशों का संकट उन्हें भारत के क़रीब लाया

भारत को लेकर क्यों नरम पड़े मुइज्जू

प्रणव ढल सामंता

अस्थिरता के भंवर में फंसे पड़ोसी मुल्कों की सूची में बांग्लादेश भी शामिल हो गया। पिछले साल मालदीव में भी कुछ ऐसे ही हालात हो गए थे, जब मोहम्मद मुइज्जू भारत विरोधी भावनाओं के सहारे सत्ता में पहुंचे। 2022 में श्रीलंका में बांग्लादेश जैसा ही दृश्य नजर आ रहा था।

भारत का बढ़ता प्रभाव | भारत ने श्रीलंका में शानदार वापसी की है। चीन के मुकाबले अब वहां भारत काफी मजबूत स्थिति में है। और अगर विदेशमंत्री एस जयशंकर के हालिया मालदीव दौरे की रोशनी में देखा जाए तो मुइज्जू भी अपनी गलती सुधारने की राह पर हैं। साफ है कि बदलती भू राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताएं भारत के बढ़ते प्रभाव की नई कहानी सुना रही हैं।

मालदीव की मुश्किलें | मई महीने में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने चीन के बढ़ते कर्ज के सिलसिले में मालदीव को चेतावनी दी। एक महीने बाद रेटिंग एजेंसी फिच ने उसकी रेटिंग कम कर दी।

संकट के आसार | विश्व बैंक की अंतरराष्ट्रीय कर्ज रिपोर्ट 2023 के मुताबिक मालदीव के कुल विदेशी कर्ज का 30 फीसदी चीन से लिया गया है जो 4 बिलियन डॉलर से ऊपर बैठता है। जिस चीनी कर्ज के जाल में श्रीलंका फंसा, उसमें कई और छोटी अर्थव्यवस्थाएं फंसीं। मुइज्जू को समझते देर नहीं लगी कि भारत की मदद की जरूरत है।

जरूरी चीजों के बढ़े दाम | इस बीच भारत पर निर्भरता कम करने के लिए पश्चिम एशिया से खाद्य आपूर्ति शुरू कराने जैसे मुइज्जू के प्रयासों के परिणाम यह हुआ कि मालदीव में इन सामानों के दाम बढ़ गए। जल्दी ही साफ हो गया कि खाद्य और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिहाज से मालदीव के लिए भारत ही सबसे अच्छा विकल्प है।

कोलंबो की मदद | श्रीलंका में वित्तीय संकट आने पर भारत ने सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया था। अहम मौकों पर लिक्विडिटी उपलब्ध कराई और फिर IMF पैकेजसुनिश्चित करने में भी सहायता की। आज श्रीलंका में महंगाई दर 3 फीसदी से नीचे है जबकि सितंबर 2022 में यह 67.4 फीसदी थी।

चुनावों पर नजर | जहां तक चीन से जुड़ी चिंताओं का सवाल है तो कोलंबो ने श्रीलंकाई समुद्री सीमा में विदेशी रिसर्च जहाजों को पहले ही बैन कर दिया है। हालांकि यह प्रतिबंध अगले साल समाप्त होने वाला है लेकिन चीन की ओर श्रीलंका के बढ़ते रुझान की समस्या अब समाप्त हो चुकी है।

आपदा में अवसर | ऐसे में दो बातें गौर करने लायक हैं। एक, किसी पड़ोसी देश में पैदा हुए किसी संकट पर भारत हमेशा काबू पा ले या उसे हल कर दे यह जरूरी नहीं है। दो, भारत ऐसे संकट को अवसर में जरूर तब्दील कर सकता है, खासकर मौजूदा भू राजनीतिक संदर्भों में। यह इसलिए भी संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में उसका आर्थिक प्रभाव भी बढ़ा है।

स्थिरता लाने में भूमिका | पिछले एक दशक में भारत ने खास तौर पर चार प्रमुख क्षेत्रों में अपनी जड़ें मजबूत की हैं- फाइनैंस, सप्लाई चेन, पेट्रोलियम और इन्फ्रास्ट्रक्चर। इन क्षेत्रों में किया गया निवेश अब राजनीतिक संकटों के दौरान स्थिरता लाने में अहम भूमिका निभाता है। इन देशों की हर सरकार संकट की स्थिति में भारत का समर्थन सुनिश्चित करना चाहती है।

मालदीव की मदद
- बढ़ता जा रहा था विदेशी कर्ज
- जरूरी चीजों के बढ़ गए थे दाम
- भारत ने जरूरत के वक्त की मदद

नेपाल में ट्रांमिशन लाइन | नेपाल में भारत ने तीन और ट्रांसमिशन लाइन स्थापित कर दी है। इससे अब काठमांडू अतिरिक्त बिजली निर्यात करने की स्थिति में आ गया है। भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच हाल ही में बिजली खरीद का एक समझौता हुआ है। त्रिपुरा के NTPC प्लांट और झारखंड (गोड्डा) के अडाणी पावर प्लांट से बांग्लादेश को सप्लाई शुरू हो चुकी है।

संप्रभुता से छेड़छाड़ नहीं | बांग्लादेश की कोई भी नई सरकार थोड़ी सी स्थिरता पाते ही भारत के साथ आर्थिक आदान-प्रदान की प्रक्रिया दुरुस्त करना चाहेगी। भारत के जितने भी संभावित विकल्प हैं, आगे चलकर ज्यादा जोखिमभरे और महंगे साबित होते हैं। चीन के विपरीत भारत न तो अपनी मदद को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है और न ही इन देशों की संप्रभुता के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ करता है। इसके अलावा यह बात भी है कि भारत का हित आर्थिक तौर पर समूद्ध पड़ोस सुनिश्चित करने में है क्योंकि इनमें से किसी भी देश में आया संकट सिर्फ उस देश की सरहदों तक सीमित नहीं रहता। उस संकट का असर भारत में भी दिखता है।

भारत के पक्ष में समीकरण | इस तरह व्यापक भू राजनीतिक समीकरण भारत के पक्ष में नजर आते हैं, आजादी के बाद शायद पहली बार ऐसा हुआ है। शेख हसीना सरकार को लेकर भारत और अमेरिका की राय अलग-अलग है। लेकिन क्या वे इस असहमति का फायदा चीन को उठाने देंगे? भारत और अमेरिका के बीच सामरिक साझेदारी की अहमियत को देखते हुए दोनों देशों का हित इसी में है कि वे इन असहमतियों को आपस में ही हल करने की कोई राह निकाल लें।

संकट का मिले फायदा | अस्थिर सरकारें निर्यात्रित नहीं की जा सकतीं। ऐसे में आर्थिक ढांचे तैयार करते चलना खासा महत्वपूर्ण हो जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर संकट सिर्फ अस्थिरता ही न लाए, रणनीतिक प्रभाव बढ़ाने का अवसर भी बने।

नई पीढ़ी को तजुर्बों की घनी छांव देते हैं बुजुर्ग

जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कहना है कि बूढ़े होने के बाद आप हंसना बंद नहीं करते, जब आप हंसना बंद कर देते हैं, तो बूढ़े हो जाते हैं। पिंडरा वाले बाबा ने हंसना बंद नहीं किया है, इसी वजह से वह अब तक बूढ़े नहीं हुए। किसी से बात करते हुए उनके चेहरे की मुस्कान कभी गायब नहीं होती। खुशी से भरी हर छोटी बात पर खिलखिलाने लगते हैं वह। किस्सों की भरमार है उनके पास, उनकी तीन-तीन नौकरियां बदलने के किस्से, घर-परिवार के किस्से, बनारस के किस्से। जब वह पुरानी बातें बता रहे होते हैं, तो केवल बात नहीं चलती बल्कि उनके साथ-साथ पुराना वक्त भी चल रहा होता है। ऐसा लगता है कि आप कोई पुरानी ब्लैक एंड वाइट फिल्म देख रहे हैं। कहानी आगे बढ़ती जाती है, बाबा खुश होते जाते हैं और सुनने वाला भी उसमें डूब जाता है। किस्सों की ऐसी ठोकरी और खुशियों का ऐसा खजाना केवल पिंडरा वाले बाबा के पास ही नहीं, बल्कि दुनिया के सभी बुजुर्गों के पास है। ऐसा खजाना है यह, जो कभी खत्म नहीं होता और जिसे बांटने में बेहद खुशी मिलती है उन्हें।

पुरानी कहावत है कि धूप में बाल सफेद नहीं किए। यह बाल सफेद हुए हैं समय की कीमत चुकाकर और इसके बदले में मिला है बेशुमार अनुभव। इस अनुभव को पाने के दो ही तरीके हैं। या तो खुद समय के साथ समझौता किया जाए, या फिर समय बिताया जाए बुजुर्गों के साथ। पहले विकल्प में सफलता के साथ असफलता का भी जोखिम छिपा है, जबकि दूसरे विकल्प से पता चल सकता है कि क्या करना है जिससे नाकामी का खतरा कम हो जाए। बुजुर्ग उस पेड़ की तरह हैं, जिन्होंने सारे तूफान, सर्दी, गर्मी

AI Image

जीवन आनंद

झेल लिए हैं। अगली पीढ़ी को वह मौका दे रहे हैं अपनी घनी छांव में आगे बढ़ने का।

किसी टाइम मशीन जैसे होते हैं बुजुर्ग। उनके साथ बैठकर उस दौर को महसूस किया जा सकता है। हमें आज लग सकता है कि यह दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है, लेकिन किसी बुजुर्ग से पूछिए, तो पता चलेगा कि उन्होंने अपने जीवन में क्या नहीं देखा। बदलाव की जिस आंधी से गुजरकर वे यहां तक पहुंचे हैं, उसके बाद अब शायद ही कोई चीज उन्हें हैरान करती हो। जब हम किसी जगह पहली बार जा रहे होते हैं, तो किसी ऐसे को तलाशते हैं, जो पहले जा चुका हो वहां। जीवन का हर आने वाला दिन वही अनजानी जगह तो है। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास बुजुर्ग हैं, जो ऐसे तमाम दिनों को पीछे छोड़ आए हैं। समय यात्रा में उनका सहयोगी बनकर हम भी तैयार हो सकते हैं भविष्य के लिए।

हमें लगता है कि गूगल के पास हर सवाल का जवाब है और AI से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई और नहीं। लेकिन, क्या जीने का सलीका, रीति-रिवाजों की समझ, लोगों को परखने का हुनर और परिस्थितियों को तौलने की क्षमता गूगल पर सर्च करके मिल सकती है? क्या कोई मशीनी दिमाग बता सकता है कि कैसे संतुलन साधा जाए जीवन में? यह कॉम्बो केवल बुजुर्गों में ही मिलेगा।

युवा मन आजाद होता है, लेकिन कुछ बंदिशों के साथ। ये बंदिशें होती हैं आने वाले कल से जुड़ी चिंताओं की, अपने को सुरक्षित रखने की। लेकिन, बुजुर्ग आजाद होते हैं इन सारी चिंताओं से और उनकी आजादी की कोई शर्त नहीं होती। उम्र बढ़ने के साथ बंदिशों की दीवार गिरती चली जाती है। इस आजादी का अहसास करना चाहते हैं तो बुजुर्गों के साथ जुड़िए, उनसे दोस्ती कीजिए। इस दोस्ती की खास बात है कि इसमें बस लेना ही लेना है, देना कुछ नहीं। और हमारे दोस्त इतने दिलदार हैं कि वह अपना सबकुछ लुटा देंगे और फिर भी खिलखिलाते रहेंगे।

शेयर करें अपने अनुभव
जीवन की दिनचर्या के अनुभवों में आप कैसे आनंद महसूस करते हैं, हमें बताएं nbtreader@timesofindia.com पर, और स्क्रीनशॉट भेजें लिखें 'जीवन आनंद'

बंधन में बांधकर आजादी दिलाता है रक्षाबंधन का पर्व

आर.डी. अग्रवाल 'प्रेमी'

श्रावण सुदी पूर्णिमा को मनाया जाने वाला रक्षाबंधन रिश्तों के बंधन का त्योहार है। भाई की कलाई पर रक्षासूत्र बांधकर बहनें उनके जीवन की खुशहाली और लंबी आयु की कामना करती हैं। इस त्योहार में पूरे समाज को एकता के सूत्र में बांधने का संदेश छिपा है। हर कोई इस त्योहार को अलग-अलग अंदाज में मनाता है। जैसे सद्गुरु अपने दरबार में शिष्य को ज्ञान रूपी रक्षासूत्र बांधकर अध्यात्म में आगे बढ़ने और जीवन को आनंदमय बनाने का आशीर्वाद देते हैं। पुरोहित अपने यजमान को मोरी या राखी बांधकर उन्हें शुभकामनाएं देते हैं।

रक्षा बांधने वाला गारंटी लेता है कि दोनों सुख-दुख में बंधन और संकट के समय साथ निभाएंगे। जब कोई साधक साधना से मन को काबू में कर लेता है, तब उसकी दसों इंद्रियां और अंदर की सब वृत्तियां स्वयं ही उसके काबू में हो जाती हैं। मन को बांध लेना भी रक्षाबंधन का एक स्वरूप है। मन के बांध लेने से जीव यम के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो जीते जी मन को काबू में नहीं करता, यानी जिसका मन चंचल रहता है और अपनी इंद्रियों को बाहरी क्रियाओं के जरिये हठ करके रोकने की कोशिश करता है, उसे गीता में दंभी और पाखंडी बतलाया गया है। वह सारा प्रयास ढोंग ही होता है, बाहरी दिखावा ही है।

सभी शास्त्र और धर्म-ग्रंथ यही बताते हैं कि महापुरुष, जो सद्गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, वे मन को बांधने का साधन या विधि बतलाते हैं। वे साधक को सच्चे बंधनों में बांधकर उसे मुक्त कर देते हैं। कहा भी गया है, 'निर्बंधा बंधा रहे, बंधा निर्बंध होय। कर्म करे कर्ता नहीं, कर्म कहावे सोय।' जो 'गुरु आज्ञा' रूपी रक्षा के बंधन में बंध जाता है, वह सचमुच सच्चे मायने में आजाद हो जाता है और सच्ची सुख-शांति और आनंद प्राप्त करता है। रक्षाबंधन वास्तव में 'वसुधैव कुटुंबकम' की अवधारणा को बड़ा आकार देता है, जिसमें पूरी दुनिया समा जाए। इसका कारण है कि रक्षाबंधन सुरक्षा और पारिवारिक प्रेम के इर्द-गिर्द घूमता है।

महाभारत में भी श्रीकृष्ण और द्रौपदी का एक प्रसंग है। जब श्रीकृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था, तब उनकी तर्जनी उंगली में चोट आ गई थी। तभी द्रौपदी ने अपनी साड़ी में से एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर पट्टी बांध दी थी। यह श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। श्रीकृष्ण ने इस उपकार का बदला बाद में चीरहरण के समय उनकी साड़ी को बढ़ाकर चुकाया।

कहते हैं कि परस्पर एक-दूसरे की रक्षा और सहयोग की भावना हमें रक्षाबंधन के पर्व से ही प्राप्त होती है। इसीलिए रक्षाबंधन का यह त्योहार हमारी परंपरा में शामिल हो गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जन जागरण के लिए रवींद्रनाथ टैगोर ने बंग-भंग का विरोध करते समय रक्षाबंधन त्योहार को बंगाल निवासियों के पारस्परिक भाईचारे और एकता का प्रतीक बनाकर आरंभ किया था।

ऐसा माना गया है कि श्रवण नक्षत्र में बांधा गया रक्षासूत्र अमरता, निडरता, स्वाभिमान, कीर्ति, उत्साह और स्फूर्ति प्रदान करने वाला होता है। सामान्य-सा दिखने वाला एक काम हमारे समाज में खुशहाली और सद्भावना की गारंटी का संदेश देता है।

बिल गेट्स ने कैसे बदली अपनी इमेज

मृत्युंजय राय

भारत में भी आर्थिक असमानता एक मुद्दा है। फाइनैंशल टाइम्स के पूर्व पत्रकार जेम्स क्रैबट्री ने अपनी किताब Billionares Raj में टॉमस पिकेटी के रिसर्च का हवाला देते हुए दावा किया था कि 1922 के बाद भारत में आर्थिक असमानता सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है। पिकेटी की रिसर्च जिस डेटा पर आधारित थी, उसे लेकर सवाल भी उठे थे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश में आर्थिक असमानता बढ़ रही है। साथ ही, यह बहस भी चल रही है कि आर्थिक असमानता कम करने के लिए क्या करना चाहिए?

AI Image

विचार विंडो

दुनिया के पहले टेक्नॉलजी बिलियनेयर बिल गेट्स की जीवनी के जरिये एक नई किताब में इन सवालों का जवाब देने की कोशिश की गई है। इस किताब का नाम है **Billionaire, Nerd, Saviour, King**, जिसे लिखा है अनुप्रिता दास ने। वह न्यूयॉर्क टाइम्स की फाइनैंस एडिटर रह चुकी हैं।

दिलचस्प बात यह है कि लेखिका ने गेट्स की शुरुआती कामयाबी पर बहुत पन्ने जाया नहीं किए हैं। यह बात काफी लोग जानते हैं कि बिल गेट्स को कामयाबी कैसे मिली। 1995 में गेट्स अमेरिका के सबसे रईस व्यक्ति बन चुके थे, लेकिन उनकी कंपनी ने अपने बिजनेस एरिया में जो एकाधिकार कायम किया हुआ था, उसे लेकर काफी आलोचना हो रही थी। बिल गेट्स जिन्हें दुनिया ने कभी उनकी कामयाबी की वजह से हीरो का दर्जा दिया था, मोनोपॉली बिजनेस की वजह से उन्हें खलनायक माना जाने लगा था। गेट्स ने अपने उद्यमिता के जीवन में कई गलतियां कीं। उनकी यही गलतियां बाद की पीढ़ी में अमीर उद्योगपतियों के लिए मिसाल बन गईं। मेटा इंक के मार्क जकरबर्ग और एमेजॉन के जेफ बेजोस ऐसे लोगों में शामिल हैं।

खैर, बिल गेट्स का मोनोपॉली विवाद के बाद एक नया अवतार सामने आया। इसमें वह अपनी ज्यादातर संपत्ति दान करने वाले उद्योगपति के रूप में नजर आए। इसी सिलसिले में दुनिया के जाने-माने निवेशक और वर्कशायर हैथवे के चेयरमैन वॉरेन बफेट भारत आए थे। उन्होंने भी अपनी ज्यादातर संपत्ति बिल गेट्स के फाउंडेशन को परोपकार के कामकाज के लिए दान कर दी है। बफेट यह भी कहते रहे हैं कि बिल गेट्स उनके करीबी दोस्त हैं, जबकि दोनों की उम्र में काफी फासला है। खैर, इस अभियान के जरिये गेट्स अपनी छवि बदलने में कामयाब रहे और 2014-2019 के बीच वह दुनिया के 'मोस्ट अडमायर्ड मैन' बने रहे।

इस किताब में मेलिंडा गेट्स के साथ उनके तलाक और Jeffrey Epstein के साथ दोस्ती को लेकर खड़े हुए विवादों के बारे में भी बताया गया है। उस कॉन्फ्लपरेसी थिअरी का भी जिक्र है, जिसने कोरोना महामारी के वक्त सिर उठाया था। इसमें कहा गया कि कोरोना से बचाव के लिए जो वैक्सीन लोगों को लगाई जा रही है, वह उससे मुनाफा कमा रहे हैं। गेट्स पर ऐसे आरोप भी लगे हैं कि उनका फाउंडेशन स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना पैसा खर्च करता है कि वह कई देशों की हेल्थ पॉलिसी को बदल रहा है। सवाल यह भी उठा कि उनका फाउंडेशन रेग्युलेट नहीं हो रहा है। इस किताब में गेट्स से जुड़ी कुछ ऐसी बातों की ओर भी ध्यान दिलाया गया है, जो मीडिया में आई तो हैं, लेकिन उन्हें बहुत तवज्जो नहीं मिली है। मसलन, गेट्स के पास अमेरिका में सबसे अधिक खेती की जमीन है। गेट्स ने इतनी जमीन क्यों खरीदी है, इसे लेकर अटकलें लगती रही हैं। अनुप्रिता दास की किताब में बिलियनेयर गेट्स के बारे में कई नई जानकारियां दी गई हैं तो इसमें दूसरे अमेरिकी रईसों के बारे में कई सबक भी हैं।

ये हैं 'मदरमोनियल्स'

प्रणव प्रियदर्शी

'वर चाहिए' और 'वधू चाहिए' वाले विज्ञापनों में गोरी, लंबी और छरहरी लड़की का वर्णन आज भी एक कड़वी हकीकत बना हुआ है। मगर इस बीच आधुनिक सोच वाले ऐसे लोगों की बिरादरी बढ़ी होती गई है जो इस तरह लड़की को ऑब्जेक्टफाई करने के खिलाफ है। ऐसे लोगों को हाल में की गई एक अनूठी पहल 'मदरमोनियल्स' खूब रास आ रही है। मैट्रिमोनियल्स के पिसे-पिटे विज्ञापनों से चिढ़ के कारण उससे दूरी रखने वाले ऐसे लोग इसी 28 जुलाई को लॉन्च किए गए 'मदरमोनियल्स' के विज्ञापनों को खेल-खेल में सोच बदलने वाली एक महत्वपूर्ण कोशिश के रूप में देख रहे हैं। हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के सौजन्य से शुरू किए गए डव के इस AI पावर्ड प्लैटफॉर्म पर शादी के ही विज्ञापन दिए जाते हैं, लेकिन बिल्कुल अलग अंदाज में। इन विज्ञापनों में लड़की को एक शरीर के रूप में नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर उसके व्यक्तित्व की खूबियों के साथ पेश किया जाता है। रंग, कद और नाक-नक्श बताने के बजाय इनमें लड़की के स्वभाव और उसकी हॉबी वगैरह के डीटेल दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर, निक्की डिमरी के परिवार के ओर से दिए गए विज्ञापन में पहले तो यह दोस्ताना चेतावनी दी गई है कि यह विज्ञापन आपको इसी के बेकार फब्तियों के बीच ले जाकर सरोवार कर सकता है और फिर कहता है, 'मिलिए पिनस्र और नेकदिल निक्की डिमरी से जो पशुओं से खास लगाव रखती है और पकाने में उस्ताद है। दिन में सपने देखने वाली यह लड़की सौंदेवाजी करने में भी प्रवीण है।' 20 साल की पल्लवी मेहता की ओर से दिया गया विज्ञापन कहता है, 'क्या आप एक प्यारे इंसान को उसकी विचित्र झपकियों के साथ बर्दाश्त कर सकते हैं?' साफ है कि शादी के ये विज्ञापन एक नई शुरुआत का एलान करते हैं। यह एलान इसलिए भी मायने रखता है कि समाज की मुख्यधारा की सोच आज भी ज्यादा नहीं बदली है। TOI के सहयोग से किया गया डव का ताजा सर्वे भी बताता है कि देश में शादी के इच्छुक 76.7 फीसदी पुरुष कंचे कद और 76 फीसदी गोरे रंग को महत्वपूर्ण मानते हैं।

AI Image

आधी दुनिया

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

परछाइयों की सीख
12 अगस्त को 'जीवन आनंद' कॉलम में प्रकाशित लेख 'परछाइयों में छिपी खुशियों को कभी तलाशा क्या' पढ़ा। प्रह्लाद आचार्य का उदाहरण देते हुए, लेखक ने दिखाया है कि कैसे परछाइयां केवल काले रंग की आकृतियां नहीं होतीं, बल्कि वे कल्पनाओं और भावनाओं के रंग भी समेटे रहती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि परछाइयां हमें अपने भीतर के विश्वास को संजोकर रखने का संदेश देती हैं। चाहे सड़क पर गंदगी हो या आलोचनाएं, परछाइयां वेझिझक चलती रहती हैं। यह विचार हमें जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

प्रीति अग्रवाल, इंमेल से

काम नहीं छोटा
5 अगस्त के लेख 'एक ट्रिक आजमाइए, काम से प्यार हो जाएगा' पढ़कर यही लगा कि किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। काम से प्यार करेंगे और उसे सम्मान देंगे तो निश्चित ही संतुष्टि और खुशियां मिलेंगी। हम जिस कार्य को करते हैं, वह सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि हमारी पहचान और जीवन की दिशा भी निर्धारित करता है। इस लेख ने काम के प्रति एक नई मानसिकता अपनाने की प्रेरणा दी है।

पवन त्यागी, नोएडा

प्रेम का अनूठा अवसर
आज रक्षाबंधन है। त्योहार जीवन में खुशियां लाने का एक अनूठा अवसर है। चूंकि उस खास दिन को सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक जश्न के रूप में मनाया जाता है, इसलिए यह हम सबको एक साथ लाते हैं। त्योहार न केवल परंपराओं और रीति-रिवाजों को जीवित रखते हैं, बल्कि वे हमें एक नए उत्साह और आनंद का अनुभव भी कराते हैं। त्योहार धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवन के महत्व को भी समझाते हैं। इस प्रकार त्योहार समाज की कमजोर होती कड़ियों को मजबूत करने का काम करते हैं।

मोहित प्रसाद, इंमेल से

जीवन आनंद

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र
चुनाव से पहले झारखंड में हो सकता है बड़ा खेल - एक खबर - हैरानी की बात नहीं, चुनावी दंगल में सब जायज है।

रोहित मिश्र

कल्पमेधा

स्वयं को कार्य में लगाए रखें। जीवन में बिना परिश्रम के कोई भी सामर्थ्यवान नहीं होता है। भूमि अगर उर्वरा है, फिर भी उसमें बिना खेती के अच्छी फसल पैदा नहीं होती है।

- प्लेटो

हादसों की रेल

अब तो रेल हादसे जैसे आए दिन की बात हो गए हैं। पिछले दो महीने में शायद ही कोई हफ्ता बीता हो, जब कहीं न कहीं कोई बड़ी रेल दुर्घटना न हुई हो। शुक्रवार और शनिवार की दरम्यानी रात को साबरमती एक्सप्रेस के बाईस डिब्बे पटरी से उतर गए। गनीमत है, उसमें कोई हताहत नहीं हुआ। हादसा कानपुर के पास रात के करीब ढाई बजे हुआ, जब गाड़ी में ज्यादातर लोग सो रहे थे। ट्रेन चालक का कहना है कि इंजन किसी भारी चीज से टकराया, वह जब तक गाड़ी रोकता, डिब्बे पटरी से उतर चुके थे। तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है कि इंजन के आगे जानवरों आदि से सुरक्षा के लिए लगा लोहे का हिस्सा टकरा कर टूट चुका है। समझना मुश्किल है कि इतना भारी पत्थर रेल की पटरियों पर आया कैसे। अगर कोई पहाड़ी इलाका होता, तो माना जा सकता था कि ऊपर से खिसक कर पत्थर वहां आ गया होगा। खैर, सच्चाई तो जांच के बाद पता चलेगी, पर असल सवाल जस का तस बना हुआ है कि आखिर रेल सुरक्षा को लेकर कब मुसाफिरों में भरोसा बन सकेगा।

वर्षों से ट्रेनों में टक्कररोधी उपकरण लगाने और पटरियों को अधिक सुगम बनाने की योजना पर काम चल रहा है। वर्तमान सरकार ने कवच नामक उपकरण विकसित किया, जिसे लगाने के बाद गाड़ियों में हादसों की आशंका शून्य होने का दावा किया जाता रहा है। मगर अभी तक यह प्रणाली कुछ ही जगहों पर लग पाई है। ट्रेनों के संचालन को कंप्यूटरीकृत करने पर जोर है, बहुत सारे रास्तों पर यह काम भी करता है। मगर कई हादसों में देखा जा चुका है कि सिग्नल प्रणाली ठीक से काम न करने की वजह से गाड़ियां आपस में टकरा गईं, तो कहीं किसी गाड़ी को गलत पटरी पर रवाना कर दिया गया। एक ही पटरी पर दो विपरित दिशाओं से गाड़ियों के आने के भी उदाहरण हैं। गाड़ियों के पटरी से उतरने की वजहें छिपी नहीं हैं। यात्रियों का दबाव कम करने के मकसद से हर वर्ष कुछ नई गाड़ियां चला दी जाती हैं। त्योहारों के वक्त विशेष गाड़ियां भी चलाई जाती हैं। फिर, माल ढुलाई के लिए रेल यातायात पर दबाव लगातार बढ़ता गया है। मगर पटरियों की क्षमता का आकलन ठीक से नहीं किया जाता। देश की ज्यादातर पटरियां अपनी क्षमता से अधिक भार वहन कर रही हैं। ऐसे में दबाव पड़ने से उनमें टूटन स्वाभाविक है।

पिछले वर्षों में रेलवे स्टेशनों को चमकाने पर जोर तो खूब दिया गया। इसमें निजी कंपनियों को भी शरीक किया गया। रेल भाड़े में बढ़ोतरी की गई, वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट समाप्त कर दी गई। इस तरह रेलवे का मुनाफा बढ़ाने का हर प्रयास किया गया। मगर रेल सुरक्षा के मामले में स्थिति दयनीय बनी हुई है। अब भी रेलों में महिलाओं के साथ दुष्कर्म, चोरी और लूट जैसी घटनाएं रुक नहीं पाई हैं। रेलों के समय पर न पहुंचने को तो जैसे लोगों ने सहज स्वीकार कर लिया है। मगर मुसाफिरों को जब यही भरोसा न हो कि वे जिस गाड़ी में बैठे हैं, वह सही-सलामत अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगी, तो रेलवे के लिए इससे बड़ी विफलता क्या हो सकती है। इस सबकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। विचित्र है कि तेज रफ्तार ट्रेनें चला कर दुनिया से होड़ करने का दम भरा जाता है, मगर मौजूदा गाड़ियों की सुरक्षा का कोई व्यावहारिक उपाय तलाशने की कोशिश नहीं होती।

बाढ़ कुप्रबंधन

हर वर्ष मानसून में बाढ़ से देश के अलग-अलग इलाकों में जैसी तबाही सामने आने लगी है, उसकी वजह नदियों में उफान और पानी का बेलगाम हो जाना है। अगर बाढ़ से बचाव के इंतजामों पर समय रहते ध्यान दिया जाए, तो इसकी वजह से जानमाल के व्यापक नुकसान से बचा जा सकता है। यह अफसोसनाक है कि जिन राज्यों में पिछले कुछ वर्षों में बाढ़ की वजह से व्यापक तबाही मची है, उनमें से कई राज्य सरकारों की चिंता में यह पक्ष शामिल नहीं रहा कि बाढ़ से होने वाले नुकसानों से बचाव के इंतजाम पहले ही कर लिए जाएं। नतीजतन, कई राज्यों में बरसात के मौसम में उफनने वाली नदियां भारी कहर ढाती हैं और व्यापक पैमाने पर जानमाल का नुकसान होता है। यों कुदरती आपदाओं से बचाव में लापरवाही को लेकर सरकारों के रुख पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं, अब जल शक्ति मंत्रालय की लोकलेखा समिति ने भी राज्यों के रवैये पर सवाल उठाया है।

गौरतलब है कि जल शक्ति मंत्रालय की बाढ़ नियंत्रण एवं पूर्वानुमान के लिए योजनाओं की लोकलेखा समिति की एक रपट में पश्चिम बंगाल सहित आठ राज्यों में बाढ़ प्रबंधन कार्यों में दस से तेरह महीनों की देरी को लेकर सवाल उठाया गया है। समिति के मुताबिक, इस देरी की वजह से वास्तविक वित्तपोषण के समय तकनीकी डिजाइन अप्रासंगिक या अप्रचलित हो गए। इस प्रवृत्ति के नतीजे में योजनाओं की लागत में भी भारी इजाफा हो जाता है। यह हैरानी की बात है कि जब बाढ़ प्रभावित इलाकों में तबाही आती है, जानमाल का व्यापक नुकसान होता है, तब संबंधित राज्य सरकारें इसे प्राकृतिक आपदा बताती और इसके लिए वित्तीय सहायता की मांग करती हैं। मगर यह समझना मुश्किल नहीं है कि अगर बाढ़ प्रबंधन से जुड़े कार्यों में करीब एक वर्ष तक की देरी की जाती है, तो उसके नतीजे क्या होंगे। यह सही है कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन अगर इससे उपजने वाली समस्याओं के संदर्भ में जरूरी प्रबंधन समय पर सुनिश्चित किए जाएं तो नुकसान को काफी कम किया जा सकता है। मगर बाढ़ प्रबंधन के मामले में खुद राज्य सरकारें समयबद्धता का ध्यान न रखें तो नतीजों का अंदाजा लगाया जा सकता है।

बरसात से बढ़ती तबाही

मौसम विभाग के मुताबिक, भारत के मुख्य मानसून क्षेत्र, जिसमें देश के अधिकांश वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र शामिल हैं, में इस मौसम में सामान्य से अधिक वर्षा होने का अनुमान है। मौसम एजंसियों को उम्मीद है कि इस महीने ला-नीना की स्थिति बन जाएगी।

योगेश कुमार गोयल

पिले कुछ दिनों से देश के कई राज्यों में मानसून आफत बनकर बरस रहा है। भारी बारिश के कारण केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन में तीन सौ से ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी, कई गांव तबाह हो गए। हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार बादल फटने की घटनाओं से तबाही का मंजर देखा जा रहा है। विभिन्न राज्यों में कावेरी, कपिला सहित कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और अनेक इलाके भीषण बाढ़ के कारण त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार देश में इस वर्ष जुलाई महीने में औसत से नौ फीसद ज्यादा बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक, भारत के मुख्य मानसून क्षेत्र, जिसमें देश के अधिकांश वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र शामिल हैं, में इस मौसम में सामान्य से अधिक वर्षा होने का अनुमान है। मौसम एजंसियों को उम्मीद है कि इस महीने ला-नीना की स्थिति बन जाएगी।

हालांकि ऐसा नहीं कि सभी राज्यों में एक समान पानी बरस रहा है। उत्तर भारत के कुछ राज्यों में लोग कम बारिश के कारण उमस भरी गर्मी से बेहाल हैं। भारतीय मौसम विभाग (आइएमडी) के आंकड़ों के अनुसार देश में 1 जून से 30 जुलाई तक कुल सात राज्यों में सामान्य से बहुत अधिक बारिश दर्ज हुई, वहीं बारह राज्यों में सामान्य बारिश हुई और आठ राज्यों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार इस बार पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से कम, उत्तर-पश्चिम में सामान्य और देश के मध्य तथा दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है।

केरल, हिमाचल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश सहित कुछ राज्यों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त है, जहां बाढ़ और बारिश के कारण सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। असम सहित पूर्वोत्तर इलाकों में बाढ़ का रौद्र रूप पिछले दिनों देखा जा चुका है। कई जगहों पर नदियां पूरे उफान पर हैं, तो कई स्थानों पर नदी किनारे बसे घर आदि जल-प्रलय में समा गए हैं। भारी बारिश के कारण कई इलाकों का संपर्क एक-दूसरे से कट गया है। एक ओर जहां पहाड़ों पर मानसूनी आफत बरस रही है, वहीं मैदानी इलाके उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। अब इसे प्रकृति की मार कहें या मानवीय करतूतों का दुष्परिणाम कि एक ओर जहां देश के कुछ इलाके अच्छी बारिश के लिए तरस रहे हैं, वहीं कुछ राज्य बारिश के कारण त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। इसे मानसून की दगाबाजी कहें या पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम कि मानूसन से होती तबाही की तीव्रता साल-दर-साल बढ़ रही है। मानसून का मिजाज इस कदर बदल रहा है कि कुछ राज्यों में जहां मानसून के दौरान महीने के अधिकांश दिन सूखे निकल जाते हैं, वहीं एक-दो दिन में ही इतना पानी बरस जाता है कि लोगों की मुसीबतें कई गुना बढ़ जाती हैं।

दरअसल, वर्षा की प्रकृति या स्वरूप में अब ऐसा बदलाव नजर आने लगा है कि बहुत कम समय में ही बहुत ज्यादा पानी बरस जा रहा है, जो प्रायः तबाही का कारण बनता है। मानूसन के बदलते

मिजाज के साथ-साथ बारिश से होती इस तबाही एक प्रमुख कारण यह भी है कि गांव हो या शहर, पहले हर कहीं बड़े-बड़े तालाब और गहरे-गहरे कुएं होते थे, जिनमें बारिश का पानी धीरे-धीरे अपने आप समा जाता था, जिससे भूजल स्तर भी बढ़ता था और बाढ़ जैसी स्थितियां भी निर्मित नहीं होती थीं। बीते कुछ दशक में विकास की अंधी दौड़ में तालाबों की जगह ऊंची-ऊंची इमारतों ने ले ली है। हमारी फितरत कुछ ऐसी हो गई है कि हम किसी भी छोटी-बड़ी आपदा के उत्पन्न होने की प्रबल आशंकाओं के बावजूद उससे निपटने की तैयारी नहीं करते। इसीलिए बदइंतजामी और प्रकृति के बदले मिजाज के कारण अब प्रतिवर्ष प्रचंड गर्मी के बाद बारिश रूपी राहत को देशभर में मानसूनी आफत में बदलते देर नहीं लगती।

> **भारी बारिश और बाढ़ अब केवल भारत की समस्या नहीं है, दुनिया भर में इससे भारी तबाही हो रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण अब अमेरिका, चीन, जर्मनी जैसे संपन्न देश भी ऐसी कुदरती आफतों के सामने अक्सर बौने नजर आते हैं। मौसमी परिवर्तन पर 'नेचर कम्युनिकेशन' में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के एक हिस्से में जहां सूखे का संकट गहराने की आशंका है, वहीं देश के बड़े हिस्से को अगले तीस वर्षों में भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है।**

वर्ष भर 'रेन वाटर हार्वेस्टिंग' का शोर तो बहुत सुनते हैं, लेकिन ऐसी योजनाएं सिरे कम ही चढ़ती हैं। इन्हीं नाकारा व्यवस्थाओं के चलते चंद घंटों की बारिश में ही दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बंगलुरू जैसे बड़े-बड़े शहरों में भी प्रायः जल-प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हर प्राकृतिक आपदा के समक्ष उससे बचाव की हमारी समस्त व्यवस्था ताश के पत्तों की भांति ढह जाती है। लगभग सभी राज्यों में प्रशासन के पास पर्याप्त बजट के बावजूद हर साल छोटे-बड़े नालों की तक की सफाई नहीं हो पाती है, जिसके चलते थोड़ी सी बारिश में ही नाले उफनने लगते हैं। ऐसे में गंभीर सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर मानसून की बारिश अपना व्यवहार क्यों बदल रही है? अतिवृष्टि और बाढ़ की स्थिति के लिए जलवायु परिवर्तन के अलावा विकास की विभिन्न परियोजनाओं के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई, नदियों में अवैध खनन आदि प्रमुख रूप से जिम्मेवार हैं, जिससे मानसून प्रभावित होने के साथ-साथ भू-क्षरण और नदियों में कटाव की बढ़ती प्रवृत्ति के चलते तबाही के मामले बढ़ रहे हैं।

भारी बारिश और बाढ़ अब केवल भारत की समस्या नहीं है, दुनिया भर में इससे भारी तबाही हो रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण अब अमेरिका, चीन, जर्मनी जैसे संपन्न देश भी ऐसी कुदरती आफतों के सामने अक्सर बौने नजर आते हैं। मौसमी परिवर्तन पर 'नेचर कम्युनिकेशन' में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के एक हिस्से में जहां सूखे का संकट गहराने की आशंका है, वहीं देश के बड़े हिस्से को अगले तीस वर्षों में भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है। अध्ययन में उत्तर भारत में सूखे का संकट गहराने और वर्ष 2050 तक देश के कई हिस्सों में 15 से 30 फीसद ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। इन अप्रत्याशित बदलावों पर चिंता जताते हुए शोधकर्ताओं ने वर्ष 2100 तक देश के बड़े हिस्से में 30 फीसद ज्यादा बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि उत्तर भारत की ही भांति दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका तथा आस्ट्रेलिया में भी आगामी 30 वर्षों में सूखे का संकट गहरा सकता है।

'पाट्सडैम इंस्टीट्यूट फार क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च' के एक अध्ययन में भी बताया गया है कि भारतीय मानसून की चाल को जलवायु परिवर्तन और ज्यादा गड़बड़ बना रहा है। अध्ययनकर्ताओं के अनुसार भारत के कई हिस्सों में अत्यधिक बारिश ने जो तबाही मचा रखी है, वह वैश्विक तापमान वृद्धि का ही दुष्परिणाम है। जलवायु परिवर्तन से मौसमी घटनाएं बढ़ रही हैं और मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के तापमान में प्रत्येक डिग्री सेल्सियस वृद्धि से मानसूनी वर्षा में करीब पांच फीसद बढ़ोतरी हो रही है। बादल फटने और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में होती बढ़ोतरी को भी जलवायु परिवर्तन से ही जोड़कर देखा जा रहा है।

जड़ता का मानस

अमित चमड़िया

बरसात के मौसम में सांप के काटने से हुई मौत की खबरें भले ही बहुत ज्यादा महत्त्व हासिल न कर पाती हों, लेकिन सांप काटने से हुई मौत से जुड़ी घटनाएं समाज की दशा और दिशा के बारे में भी बताती हैं। ज्यादातर मामलों में सांप काटने से किसी व्यक्ति की मौत इसलिए हो जाती है कि लोग अस्पताल न जाकर झाड़-फूंक और मंत्र से ठीक करने का दावा करने वाले तांत्रिकों के पास चले जाते हैं। इसी क्रम में सही इलाज नहीं मिल पाता है और वक्त ज्यादा बीतने के साथ सर्पदंश के शिकार लोगों की मृत्यु हो जाती है। निश्चित रूप से किसी की असामयिक मृत्यु पीड़ा पहुंचाती है, लेकिन उससे ज्यादा दुख की बात तब होती है, जब लोग अंधविश्वास में फंसकर झाड़-फूंक और मंत्र में विश्वास करके इलाज के लिए तांत्रिक के पास चले जाते हैं। वहां जाने के बाद बच सकने वाले लोग भी कई बार नहीं बच पाते हैं। समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी इसी झाड़-फूंक और तंत्र-मंत्र में विश्वास करता है।

ऐसा केवल सांप के काटने पर ही नहीं, किसी अन्य वजह से भी बीमार होने और ज्यादा समय तक ठीक नहीं होने पर लोग तंत्र-मंत्र का सहारा लेते हैं। ऐसे में कई बार ठीक होने वाली बीमारी भी बिगड़ जाती है और मरीज की मौत हो जाती है। यों सांप काटने से जान जाने की ज्यादातर घटनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं और गरीब दलित-पिछड़े लोग इसके ज्यादा शिकार होते हैं। एक खबर के मुताबिक वर्ष 2019 में पूरी दुनिया में सर्पदंश की चपेट में आए तिरसठ हजार लोगों की मौत हो गई। इसमें अस्सी फीसद यानी इक्यावन हजार लोगों की मौत अकेले भारत में हुई। मरने वालों की संख्या निश्चित रूप से बहुत कम की जा सकती है, अगर पीड़ित को सही समय पर उचित इलाज मिल जाए। ऐसी खबरें अक्सर पढ़ने को मिल जाती हैं, जिसमें लोग अपनी हर प्रकार की समस्या के समाधान के लिए तांत्रिक और 'बाबाओं' की मदद लेते हैं। आज भी छोटे शहरों में तोता द्वारा निकाली हुई पर्ची पर लिखी बात को लोग अपनी किस्मत समझ लेते हैं। तोता अपने आप को कितना खुशनसीब समझता होगा कि वह कैसे लोगों की किस्मत का फैसला अपनी 'चुहलबाजी' से करता है। धार्मिक स्थलों पर झाड़-फूंक करने वाले बाबाओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जो जटिल से जटिल रोगों का इलाज करने का दावा करते रहते हैं।

हम कहने को आधुनिक भारत में रह रहे हैं, लेकिन आज देश का एक खासा हिस्सा मानसिक रूप से जड़ अवस्था में सोचता-समझता है और कई बार बहुत बीमार अवस्था में जी रहा लगता है। कुछ समय पहले की एक घटना है। तमिलनाडु के एक गांव के मंदिर में एक नींबू पैंतीस हजार रुपए में नीलाम हुआ, क्योंकि मान्यता है कि सबसे अधिक बोली लगाकर नींबू प्राप्त करने वाले इंसान को आने वाले वर्षों के लिए धन और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा माना जाता है कि नींबू में एक अजीब 'जादू' है, जिसे लोग हरी मिर्च के साथ धागे में बांधकर घर और दुकान के बाहर या गाड़ी पर लटका देते हैं, ताकि बुरी नजर से बचा जा सके। इसे 'नजरबट्टू' भी कहते हैं। बिहार के एक छोटे से शहर सासाराम में एक महिला सप्ताह में केवल शनिवार के दिन धागे में बांधकर हरी मिर्च और नींबू को बेच कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सप्ताह के सिर्फ एक दिन धागे में बंधा नींबू खरीदने वाले लोगों की तादाद अच्छी-खासी है। इस तरह के नींबू और हरी मिर्च को वैसे लोग भी खरीदते हैं जो अपने खाने के लिए नींबू खरीदने से परहेज करते हैं। ऐसे उदाहरण हर जगह देखे जा सकते हैं। अगर इसे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसी कई तरह की 'खूबसूरत' तस्वीरें देश के अलग-अलग हिस्सों में देखने को मिल जाएंगी, जिनकी आम स्वीकृति प्राप्त है।

दुनिया मेरे आगे

> **समाजशास्त्र की अवधारणा 'सांस्कृतिक विडंबना' हमारे समाज के लिए एकदम सटीक बैठ रही है। इस अवधारणा के अनुसार हम भौतिक रूप से बहुत आगे निकल रहे हैं, लेकिन अभौतिक रूप से, मतलब वैचारिक रूप से हम पीछे होते जा रहे हैं। भौतिक और अभौतिक तत्त्वों के बीच खाई बढ़ती जा रही है।**

कई बार ऐसा लगता है कि हम सिर्फ कहने को आधुनिक हैं। लोगों में अंधविश्वास दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। हम हाथ में सबसे आधुनिक तकनीक से बने यंत्र को हमेशा अपने पास रखते हैं और अपने को तकनीक आधारित विज्ञान का झंडाबरदार मानते हैं, लेकिन हमारी तार्किकता धीरे-धीरे खत्म हो रही है। जो भी हमें परंपरा से दे दिया जाता है, हम बिना सवाल के उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। फिर वह हमारे मनोविज्ञान का हिस्सा हो जाता है और हम उसे लेकर अनुकूलित हो जाते हैं। इसके बाद उसके सही, गलत होने के सवाल हमें असहज करने लगते हैं और हम आंख मूंद कर उसका पालन करते हैं। सर्पदंश के बाद डाक्टर के पास जाने के बजाय झाड़-फूंक या तंत्र-मंत्र के जरिए ठीक करने का दावा करने वाले तांत्रिकों के पास जाना भी इसी का एक हिस्सा है। समाजशास्त्र की अवधारणा 'सांस्कृतिक विडंबना' हमारे समाज के लिए एकदम सटीक बैठ रही है। इस अवधारणा के अनुसार हम भौतिक रूप से बहुत आगे निकल रहे हैं, लेकिन अभौतिक रूप से मतलब वैचारिक रूप से हम पीछे होते जा रहे हैं। भौतिक और अभौतिक तत्त्वों के बीच खाई बढ़ती जा रही हैं। इससे समाज में एक असंतुलन पैदा हो रहा है और जब-जब इस तरह का असंतुलन बढ़ता जाएगा, समाज अंधविश्वास की गिरफ्त में कसता जाएगा।

न्याय की गति

कोई देश या समाज अपने उद्देश्यों में तभी महान बनता है, जब वह अपने यहां न्याय स्थापित करता है। हाल ही में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में जानकारी दी है कि देश में पांच करोड़ मामले लंबित पड़े हुए हैं। निचली अदालतों का तो आलम और भी चिंताजनक है। हमें विचार करना होगा कि आजादी के बाद भी हमारे यहां न्याय व्यवस्था इतनी लचर कैसे है। हमने बीते सालों में देखा है कि न्यायिक सक्रियता में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अब हर छोटे मामलों को सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर लाया जाता है। सवाल है फिर सरकारों को हम क्यों चुनते हैं। हर काम सुप्रीम कोर्ट करेगा तो कार्यपालिका की क्या प्रासंगिकता? दूसरा बड़ा कारण है न्याय व्यवस्था में कर्मचारियों की कमी को पूरा नहीं कर पाना। फिर देश की जटिल कानूनी व्यवस्था के चलते भी मामले लटके रहते हैं। समाज में लगातार अपराध में इजाफे के साथ-साथ पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार का व्याप्त होना भी इस स्थिति के कारणों में हैं। इन्हीं कारणों से हमारे देश में न्याय की दर नकारात्मक है। इसलिए सरकार और सर्वोच्च न्यायालय को मिलकर इस समस्या के हल का रास्ता निकालना चाहिए।

- सौरभ बुंदेला, भोपाल

मंदी की आशंका

दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका के ऊपर आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ता जा रहा है। तमाम अर्थशास्त्रियों के द्वारा मंदी के अनुमानों के बीच अब रेटिंग एजंसी ने भी आशंका बढ़ा दी है। इसी के चलते अमेरिका के शेयर बाजार से चली सुनामी पूरी दुनिया के शेयर बाजारों को हिलाने लगी है। एक रपट के अनुसार अर्थशास्त्रियों ने अगले साल अमेरिका में मंदी आने के अनुमान को पंद्रह फीसद से बढ़कर पच्चीस फीसद कर दिया है। हालांकि राहत की बात यह है कि अर्थव्यवस्था के ऊपर मंदी के जोखिम के बाद भी अचानक किसी बड़े नुकसान का जोखिम नहीं नजर आ रहा है। कह सकते हैं कि दुनिया भर में अमेरिकी मंदी का काफी बुरा असर पड़ेगा और इससे कई देशों की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा नुकसान होगा। इसी तरह से उनकी मुद्रा की कीमत भी लगातार घटेगी। नए बनते वैश्विक हालात के मद्देनजर अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने लिए चौकस रहने की जरूरत है।

- एमएम रजावतलज, शाजापुर, मप्र

उपयोगिता का पाठ

देश में शिक्षा का गिरता स्तर बहुत ही चिंतनीय विषय है। हमारे नीतिज्ञों, किशोरों को नैतिक चारित्रिक निर्माण और जीवन मूल्य पर आधारित शिक्षा देकर हमें बुनियादी स्तर से ही शिक्षा में सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि बच्चों और किशोरों में बढ़ती अपराध की प्रवृत्ति पर लगाम लग सके। परीक्षा पद्धति में भी आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। साल भर पढ़ाई करने के बाद परीक्षा में सिर्फ पांच-दस प्रश्नों का उत्तर देने से बुद्धि कौशल या ज्ञान नहीं मिलता है। परीक्षा समग्र शिक्षा रटने के बजाय वैचारिक समझ और अनुभवजन्य ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। अभी शिक्षा का मतलब सिर्फ भारी-भरकम फीस लेकर डिग्री प्रदान करना रह गया है। रोजगार, कौशल पेशेवर दक्षता प्रदान करने में शून्य है, उस डिग्री की वास्तविक जीवन में कोई अहमियत नहीं रहती है। छात्र डिग्री लेकर निकलते हैं तब मालूम होता है नौकरी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा का कोई महत्त्व नहीं है।

- अरविंद जैन 'बीमा', उज्जैन

भीड़ का प्रबंधन

बिहार के जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड अंतर्गत वाणावर पर्वत पर सिद्धेश्वर नाथ मंदिर परिसर में हुई भगदड़ में आठ श्रद्धालुओं की मौत और दर्जनों का घायल होना हृदयविदारक है। सावन माह में सोमवार को जलाभिषेक करने के दौरान मंदिर के मार्ग पर कई अस्थायी दुकाने सजी हुई थीं। खबरों के मुताबिक, फूल विक्रेता और शिव भक्त के बीच नोक-झोंक झगड़ा में तब्दील हो गया एवं भगदड़ मच गई। इस हादसे के लिए मंदिर प्रबंधन और प्रशासन जिम्मेदार है। घटना के वक्त पर्याप्त सुरक्षा बलों की अनुपस्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी भी प्रशासन पूर्व की घटनाओं से सबक नहीं लेती है। प्रमुख धार्मिक स्थलों पर विशेष पूजा के दौरान भीड़ जुटना एक सामान्य बात है। भीड़ प्रबंधन के लिए सही व्यवस्था होनी चाहिए। इस घटना के जिम्मेदार लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

- हिमांशु शेखर, केसपा, गया